Kamal.Sandesh kamalsandesh.org KamalSandesh

कमल संदेश

वर्ष-18, अंक-14 16-31 जुलाई, 2023 (पाक्षिक) ₹20

‘भूपेश बघेल सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है’

‘दल से पहले देश’

भाजपा मुख्यालय (नई दिल्ली) में 06 जुलाई, 2023 को डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा

खरगौन (मध्य प्रदेश) में 30 जून, 2023 को एक भव्य रोड शो के दौरान भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा

भरतपुर (राजस्थान) में 29 जून, 2023 को भाजपा कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद एक विशाल सभा को संबोधित करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा

लखनऊ (उत्तर प्रदेश) में 02 जुलाई, 2023 को डॉ. सोनेलाल पटेल जी की 74वीं जयंती के अवसर पर 'जन स्वाभिमान दिवस' कार्यक्रम के दौरान अभिवादन स्वीकार करते केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह

लखीसराय (बिहार) में 29 जून, 2023 को एक विशाल जनसभा को संबोधित करने के बाद जनता का अभिवादन स्वीकार करते केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह

कांकेर (छत्तीसगढ़) में 01 जुलाई, 2023 को एक विशाल जनसभा के दौरान अभिवादन स्वीकार करते रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह

कमल संदेश

पाक्षिक पत्रिका

संपादक
प्रभात झा

कार्यकारी संपादक
डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सह संपादक
संजीव कुमार सिन्हा
राम नयन सिंह

कला संपादक
विकास सैनी
भोला राय

डिजिटल मीडिया
राजीव कुमार
विपुल शर्मा

सदस्यता एवं वितरण
सतीश कुमार

इ-मेल
mail.kamalsandesh@gmail.com
mail@kamalsandesh.com
फोन: 011-23381428, फैक्स: 011-23387887
वेबसाइट: www.kamalsandesh.org

विषय-सूची

06 हमें सेवा भाव से बूथ के लोगों से संपर्क स्थापित करना चाहिए: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 'मेरा बूथ, सबसे मजबूत' कार्यक्रम में कहा कि आज मैं एक साथ बूथ पर काम करने वाले 10 लाख कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहा हूं। शायद किसी भी राजनीतिक दल के इतिहास में ग्रास रूट लेवल पर व्यवस्थित...

10 अल्पकालिक विस्तारक संगठन की मजबूती के लिए काम करेंगे : जगत प्रकाश नड्डा

भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित 'मेरा बूथ,...

11 भारत और मिस्र ने 'रणनीतिक साझेदारी' पर किए हस्ताक्षर

अरब गणराज्य मिस्र के राष्ट्रपति श्री अब्देल फतह अल-सिसी ने 25 जून, 2023 को अल-इत्तिहादिया पैलेस में प्रधानमंत्री...

13 भूपेश बघेल सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है : जगत प्रकाश नड्डा

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 30 जून, 2023 को बिलासपुर, छत्तीसगढ़ के नॉर्थ ईस्ट रेलवे इंस्टीट्यूट,...

29 दिल्ली विश्वविद्यालय सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं है, बल्कि एक आंदोलन है: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 30 जून को दिल्ली विश्वविद्यालय के खेल परिसर के...

वैचारिकी

अंधेरा छंटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा / **अटल बिहारी वाजपेयी** 23

श्रद्धांजलि

राज्यसभा सांसद हरद्वार दुबे नहीं रहे 25

लेख

एनईपी 2020 भारत के बच्चों के भविष्य को बदल रहा है / **विष्णु दत्त शर्मा** 30

अन्य

'कांग्रेस सरकार ने राजस्थान को भ्रष्टाचार में नंबर वन बना दिया है' 14

छत्तीसगढ़ सरकार वामपंथी उग्रवाद को लेकर गंभीर नहीं है: राजनाथ सिंह 14

कांग्रेस की इस 3'D' वाली सरकार को उखाड़ फेंकना है : अमित शाह 15

संगठनात्मक नियुक्तियां 17

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने विदेशी मिशनों के राजनयिक प्रमुखों से मुलाकात की 18

किसानों के लिए 3,70,128.7 करोड़ रुपये की नवीन योजनाओं को मिली मंजूरी 19

पिछले नौ वर्षों में देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई लगभग 59 प्रतिशत बढ़ी 19

प्रधानमंत्री ने पांच नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना 20

मोदी स्टोरी 22

चीनी सीजन 2023-24 के लिए 315 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य को मिली मंजूरी 31

प्रकाशक एवं मुद्रक: डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा मुद्रित, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास के लिए डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा प्रकाशित, एच.टी. मीडिया लिमिटेड, प्लॉट नं.-8, उद्योग विहार, ग्रेटर नोएडा (उ.प्र.)-201306 से मुद्रित एवं डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी.-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। सम्पादक- प्रभात झा

सोशल मीडिया से

नरेन्द्र मोदी

गरीबों के पक्के घर हों या कम खर्च में इलाज की सुविधा, बीते 9 वर्षों में हमने आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई हैं।

(7 जुलाई, 2023)

जगत प्रकाश नड्डा

विगत 9 वर्ष में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में समावेशी, सर्वस्पर्शी व सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हुआ है। भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता जन-जन के उत्थान को संकल्पित है।

(1 जुलाई, 2023)

अमित शाह

गहलोत सरकार भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। यह सरकार गरीब बच्चों का अनाज और वृद्धों की पेंशन तक खा गयी।

(30 जून, 2023)

राजनाथ सिंह

कारगिल युद्ध के दौरान साहसपूर्वक लड़ने और अपने प्राणों की आहुति देने वाले कैप्टन विक्रम बत्रा को याद कर रहे हैं। उनकी बहादुरी हमें प्रतिदिन प्रेरित करती है। उनके 'बलिदान दिवस' पर उन्हें मेरी श्रद्धांजलि।

(7 जुलाई 2023)

बी.एल. संतोष

जब लॉबी और उनके आका भारत को नकारात्मकता के रंग में रंगने में व्यस्त थे, तब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी भारत में तकनीक लेकर आ रहे थे। जीई एयरोस्पेस और एचएएल संयुक्त रूप से लड़ाकू जेट इंजन का उत्पादन करेंगे, यह उनमें से एक है।

(23 जून, 2023)

सर्बानंद सोनोवाल

भारत की आबादी का लगभग 18 प्रतिशत हिस्सा 72 तटीय जिलों में रहता है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय का महत्वाकांक्षी सागरमाला कार्यक्रम तटीय समुदायों के लिए रोजगार के अवसर, आजीविका और खुशहाली लेकर आ रहा है।

(05 जुलाई, 2023)

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सैफ चैंपियनशिप 2023 जीतने पर भारतीय फुटबॉल टीम को बधाई दी, 5 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया: "भारत एक बार फिर चैंपियन बना! ब्लू टाइगर्स ने सैफ चैंपियनशिप 2023 में सर्वोच्च स्थान हासिल किया! हमारे खिलाड़ियों को बधाई! इन एथलीटों के दृढ़ संकल्प और दृढ़ता से संचालित भारतीय टीम की उल्लेखनीय यात्रा, भविष्य के खिलाड़ियों को प्रेरित करती रहेगी।"

संपादकीय

देश में हो रहा व्यापक परिवर्तन

आज जबकि जन-जन का विश्वास प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में निरंतर दृढ़ से दृढ़तर होता जा रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं कि विपक्ष के एक वर्ग का लोकसभा चुनावों से पूर्व एक साथ आने का प्रयास निष्फल रहेगा। कोई भी राजनीतिक गठजोड़ जिसमें जनता की सेवा करने का लक्ष्य न होकर येन-केन प्रकारेण सत्ता हथियाने का लक्ष्य हो और वह भी कुछ वंशवादी राजनेताओं उनके परिवारों के लिए, उसे हमेशा जनता द्वारा ठुकराया ही जाएगा। बिहार में एक गठजोड़ बनाने के लिए जो लोग इकट्ठा हुए थे, उनके चेहरे कई तरह के घपलों एवं घोटालों से पहले ही दागदार हो चुके हैं। ये वही लोग हैं जो जनता नहीं बल्कि जातियों के नाम पर गिने-चुने परिवारों का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा जिनकी राजनैतिक विश्वसनीयता पर बड़े-बड़े प्रश्नचिह्न लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं भाजपा को रोकने का स्वप्न देखने के सिवा इनका कोई एजेंडा नहीं है। देश को यह पता है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध कड़े कदम उठाने के कारण ही ये लोग हाथ मिलाने को बाध्य हो रहे हैं, ताकि कानून के शिकंजे से बच सकें। चूंकि यह प्रयास कुछ सत्ता केंद्रित स्वार्थी तत्वों द्वारा किया जा रहा है, इसलिए शुरुआत से ही इनके अंदर का अंतर्विरोध भी सामने आ रहा है। इनके एजेंडे में जनहित एवं जनसेवा दूर-दूर तक नहीं है।

> **देश को न केवल कांग्रेसनीत यूपीए के लूट-खसोट, भ्रष्टाचार, पॉलिसी पैरालिसिस एवं कुशासन के दल-दल से बाहर निकाला गया है, बल्कि भारत अब एक आत्मविश्वास से भरे एवं अपनी आकांक्षाओं को पूर्ण करने में समर्थ राष्ट्र के रूप में जाना जा रहा है**

पिछले नौ वर्षों में पूरे देश में हर ओर व्यापक परिवर्तन दिखाई दे रहा है। एक ओर जहां देश को आगे ले जाने की प्रतिबद्धता के साथ जनसेवा के लिए समर्पण से देश में एक नई राजनैतिक संस्कृति का उदय हुआ है जिससे देश की राजनीति परिवर्तित हो रही है, वहीं दूसरी ओर जन-जन में अपना पूर्ण योगदान करने की कार्य-संस्कृति राष्ट्रीय जीवन को प्रेरित कर रही है। परिणाम यह है कि देश को न केवल कांग्रेसनीत यूपीए के लूट-खसोट, भ्रष्टाचार, पॉलिसी पैरालिसिस एवं कुशासन के दल-दल से बाहर निकाला गया है, बल्कि भारत अब एक आत्मविश्वास से भरे एवं अपनी आकांक्षाओं को पूर्ण करने में समर्थ राष्ट्र के रूप में जाना जा रहा है। 'फ्रेजाइल फाइव' से 'टॉप फाइव' की यात्रा और वह भी कोरोना वैश्विक महामारी के बावजूद, एक ऐसी उपलब्धि है जिसे सभी अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ एवं एजेंसियां स्वीकार कर रही हैं। विश्लेषकों को हर क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां अचंभित कर रही हैं, जिसका मुख्य कारण यह है कि केवल नौ वर्ष पूर्व भारत की इन चमत्कारी उपलब्धियों की कल्पना भी संभव नहीं थी।

भारत न केवल पिछले नौ वर्षों में विश्व की दसवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से छलांग लगाकर पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बना है, बल्कि इसकी समृद्धि से लोगों में आय के स्रोत और साधन में गुणात्मक वृद्धि हुई है तथा समृद्धि के फल समाज के नीचले पायदान तक पहुंच रहे हैं। आज जब देश का निर्यात अभूतपूर्व स्तर तक पहुंचा है, तब इसका लाभ किसान से लेकर युवाओं को रोजगार के रूप में प्राप्त हो रहा है। अब जबकि भारत विश्व का सर्वाधिक तेज गति से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था है, जल्द ही यह तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाली है। भारत की अवसंरचना का तेज विकास एवं देश में हुए डिजिटल क्रांति से तीव्र आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है, जिससे करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला जा रहा है।

भाजपा द्वारा 'मेरा बूथ, सबसे मजबूत' अभियान का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ठीक ही कहा कि यदि कोई देश के राजनैतिक परिवारों के बच्चों का विकास चाहता है तो वे विपक्षी दलों को वोट दे सकते हैं, लेकिन यदि कोई अपने बच्चों का विकास चाहता है तो उन्हें भाजपा को वोट करना चाहिए। आज पूरे देश में भाजपा एकमात्र ऐसा राजनैतिक दल है जिसमें आंतरिक लोकतंत्र है, जो राजनैतिक परिवारों एवं भाई-भतीजावाद से लड़ रहा है तथा जिसकी शक्ति करोड़ों निःस्वार्थ एवं प्रतिबद्ध कार्यकर्ता हैं। एक आंदोलन के रूप में भाजपा करोड़ों कार्यकर्ताओं की साधना का प्रतीक है और इसका नेतृत्व कठोर परिश्रम, देश के लिए समर्पण एवं राष्ट्र की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करता है। आज जब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के करिश्माई एवं सुदृढ़ नेतृव में भारत 'पंच प्रण' से अभिषिक्त है, अपने 'अमृतकाल' में राष्ट्र करोड़ों लोगों के आशीर्वाद के साथ अपनी गौरवशाली यात्रा पर चल पड़ा है। ■

shivshaktibakshi@kamalsandesh.org

‘मेरा बूथ, सबसे मजबूत’, भोपाल (मध्य प्रदेश)

हमें सेवा भाव से बूथ के लोगों से संपर्क स्थापित करना चाहिए : नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 27 जून, 2023 को भोपाल (मध्य प्रदेश) के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम (लाल परेड मैदान) के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में भाजपा द्वारा आयोजित राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम ‘मेरा बूथ, सबसे मजबूत’ कार्यक्रम का शुभारंभ किया और मध्यप्रदेश के 64,100 बूथ सहित देश भर के 543 लोकसभाओं के लगभग 10 लाख बूथों पर उपस्थित पार्टी के बूथ कार्यकर्ताओं के साथ डिजिटली संवाद किया। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने कार्यक्रम में प्रधानमंत्रीजी का स्वागत किया। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री वी.डी. शर्मा सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री तथा अल्पकालीन विस्तारक के रूप में निकल रहे पार्टी के हजारों कार्यकर्ता उपस्थित थे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ‘मेरा बूथ, सबसे मजबूत’ कार्यक्रम में कहा कि आज मैं एक साथ बूथ पर काम करने वाले 10 लाख कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहा हूं। शायद किसी भी राजनीतिक दल के इतिहास में ग्रास रूट लेवल पर व्यवस्थित तरीके से इतना बड़ा कार्यक्रम कभी नहीं हुआ होगा, जितना बड़ा आज यहां हो रहा है। भाजपा की सबसे बड़ी ताकत आप सभी कार्यकर्ता हैं। आप सिर्फ दल ही नहीं, देश के संकल्पों की सिद्धि के भी सिपाही हैं। भाजपा के हर कार्यकर्ता के लिए देशहित सर्वोपरि है, दल से बड़ा देश है।

हमें गरीब को मुसीबत से मुक्त करना है

मध्य प्रदेश के दमोह से पार्टी कार्यकर्ता श्रीराम पटेल के प्रश्न के उत्तर में प्रधानमंत्रीजी ने कहा कि बूथ अपने आप में बहुत बड़ी इकाई है। हम भाजपा के कार्यकर्ता एसी (AC) में बैठक नहीं करते हैं, बल्कि गांव-गांव जाकर हर मौसम में जनता के बीच खुद को खपाते हैं। बूथ के लिए तू-तू, मैं-मैं नहीं बल्कि सेवा भाव से पहचान होनी चाहिए। लोगों को जो काम छोटे लगते हैं, वो बहुत उपयोगी होते हैं। हमें सेवा भाव से बूथ के लोगों से संपर्क स्थापित करना चाहिए और उनके सुख-दुःख में काम आना चाहिए।

आंध्र प्रदेश के भाजपा कार्यकर्ता श्रीसाला रामकृष्णा के प्रश्न के जवाब में प्रधानमंत्रीजी ने कहा कि कार्यकर्ता के दिल में और ज्यादा काम करने की भूख होना बड़ी ताकत की बात है। भारत विकसित तभी होगा, जब गांव विकसित होगा। इसके लिए हमें गांव से काम करना होगा। लोगों को बैंकों से मदद कैसे दिलवाएं। उनको आर्थिक सहायता

‘कमल संदेश’ पढ़ें और इसे प्रसारित करें

बूथ की गतिविधियों के विस्तार और सामंजस्य पर पूछे एक प्रश्न का उत्तर देते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि बूथ स्वयं विभिन्न मुद्दों की पहचान करने के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में कार्य करता है। प्रधानमंत्रीजी ने ‘कमल संदेश’ का नाम लेते हुए कहा कि बूथ परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम कर सकते हैं और बूथ कार्यकर्ताओं को परिवर्तन के अग्रदूत बनने के लिए पहल करनी चाहिए। बूथ शिक्षा और सूचना के प्रमुख केंद्र के रूप में काम कर सकते हैं, जहां सामूहिक रूप से समाचार पत्र और पत्रिका पढ़ने को बढ़ावा दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बूथ स्तर पर प्रत्येक कार्यकर्ता को ‘कमल संदेश’ जैसी हमारी पार्टी की पत्रिकाएं पढ़नी चाहिए और इसका अधिकतम उपयोग करने के लिए इसे अन्य लोगों के साथ साझा करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि ये बूथ जमीनी स्तर पर फीडबैक के लिए एक तंत्र के रूप में काम करते हैं। बूथों का ही महत्व है कि उज्ज्वला योजना को इतने बड़े पैमाने पर लागू किया जा सका, जिससे सभी को स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन उपलब्ध हो सका। गांवों तक यूरिया के कुशल परिवहन को सक्षम करने के लिए वाहन पूलिंग भी एक ऐसी चीज है, जिसे बूथ स्तर पर लागू किया जा सकता है, जो कृषि से संबंधित विभिन्न मुद्दों के समाधान को बढ़ावा दे सकता है।

कैसे मिलती है, ये बताएं। भारत में बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, लेकिन भाजपा कार्यकर्ता ये सोचें कि मेरे बूथ पर कोई बच्चा ड्रॉप-आउट नहीं होगा। हमें इसके बारे में सोचना चाहिए कि हम गांव के अंदर कुपोषण कैसे मिटा सकते हैं। हम जन्मदिन आंगनबाड़ी में मना सकते हैं, पुण्यतिथि आंगनबाड़ी में मना सकते हैं, शादी की सालगिरह आंगनबाड़ी में मना सकते हैं। घर से कुछ अच्छा बनाकर आंगनबाड़ी में ला सकते हैं और बच्चों को खिला सकते हैं। इससे आपको आनंद भी आएगा और इन बच्चों का कुपोषण भी कम होगा।

हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें गरीब को मुसीबत से मुक्त करना है। हमारा लक्ष्य किसी एक योजना का लाभ देना नहीं, बल्कि सभी का लाभ देने का है जिसके वो वो हकदार हैं

सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के संबंध में बिहार से पार्टी कार्यकर्ता रिपु सिंह के एक प्रश्न का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें गरीब को मुसीबत से मुक्त करना है। हमारा लक्ष्य किसी एक योजना का लाभ देना नहीं, बल्कि सभी का लाभ देने का है जिसके वो वो हकदार हैं। योजनाओं की जानकारी देने के लिए सोशल मीडिया पर गांव का, बूथ का ग्रुप बना सकते हैं। नमो ऐप पर अनेक योजनाओं की जानकारी उन्हें दे सकते हैं।

जब सबका भला होगा, तो देश आगे बढ़ेगा

प्रधानमंत्रीजी ने उत्तराखंड से पार्टी कार्यकर्ता हिमानी वैष्णव के तुष्टीकरण और संतुष्टीकरण से संबंधित प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि एक तरफ वे लोग जो तुष्टीकरण करके अपने स्वार्थ के लिए छोटे-छोटे कुनबे दूसरों के खिलाफ खड़े कर देते हैं, दूसरी तरफ हम भाजपा के लोग हैं, हमारे संस्कार अलग हैं, हमारे संकल्प बड़े हैं। हमारी प्राथमिकता दल से पहले देश की है। जब देश का भला होगा, तो सबका भला होगा। जब सबका भला होगा, तो देश आगे बढ़ेगा। इसलिए भाजपा ने तय किया है कि हमें तुष्टीकरण के रास्ते पर नहीं चलना है। हम मानते हैं कि देश का भला करने का रास्ता तुष्टीकरण नहीं है, तुष्टीकरण नहीं है, तुष्टीकरण नहीं है... सही रास्ता है संतुष्टीकरण, संतुष्टीकरण, संतुष्टीकरण। आज देश में जहां भी भाजपा की सरकारें हैं, वहां हम संतुष्टीकरण में लगे हैं।

‘सबका साथ, सबका विकास’ की भावना से काम

उत्तर प्रदेश से पार्टी कार्यकर्ता रानी चौरसिया के तीन तलाक, यूनिफॉर्म सिविल कोड और वोटबैंक की राजनीति के संबंध में पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में श्री मोदी ने कहा कि जो तीन तलाक की वकालत करते हैं, वे लोग मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। तीन तलाक से पूरा परिवार तबाह हो जाता है। तीन तलाक का इस्लाम से संबंध होता तो दुनिया के मुस्लिम बहुल्य देश इसे खत्म नहीं करते। मिस्र में 90% से ज्यादा सुन्नी मुस्लिम हैं। आज से 80-90 साल पहले वहां तीन तलाक की प्रथा समाप्त हो चुकी है। अगर तीन तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है, तो पाकिस्तान, इंडोनेशिया,

कतर, जॉर्डन, सीरिया, बांग्लादेश में क्यों नहीं है। मुस्लिम बेटियों पर तीन तलाक का फंदा लटकाकर कुछ लोग उन पर हमेशा अत्याचार करने की खुली छूट चाहते हैं। यही लोग तीन तलाक का समर्थन भी करते हैं। मैं जानता हूं, इसीलिए ही मेरी मुस्लिम बहनें, बेटियां भाजपा और मोदी के साथ खड़ी हैं।

उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? सुप्रीम कोर्ट भी कॉमन सिविल कोड लाये जाने की बात करती है। प्रधानमंत्रीजी ने पसमांदा मुसलमान भाई-बहनों की स्थिति पर भी चिंता जताई और कहा कि भाजपा देश के हर नागरिक के लिए 'सबका साथ, सबका विकास' की भावना से काम कर रही है। आज सभी पसमांदा भाइयों को भी सरकार की हर योजना का लाभ मिल रहा है। भाजपा के कार्यकर्ता जब इन तथ्यों और तर्कों के साथ मुसलमान भाई-बहनों के पास जाएंगे, तो उन्हें ज्यादा बेहतर तरीके से समझाएंगे और उनका भ्रम भी दूर होगा।

बौखलाए हुए हैं विपक्षी दल

विपक्ष के एकजुट होने को लेकर गुजरात से पार्टी कार्यकर्ता हेजल जानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में प्रधानमंत्रीजी ने कहा कि भाजपा के घोर विरोधी दलों में, दोनों चुनाव (2014 और 2019) में इतनी छटपटाहट नहीं दिखी, जितनी आज दिख रही है। विपक्षी दलों की घबराहट और उनकी हरकतों से साफ है कि देश की जनता ने 2024 की चुनाव में भाजपा को वापस लाने का मन बना लिया है। 2024 में फिर एक बार भाजपा की प्रचंड विजय तय है। इसी वजह से ये सारे विपक्षी दल बौखलाए हुए हैं।

> **जिसने गरीब को लूटा है, जिसने देश को लूटा है, उसका हिसाब होकर रहेगा। आज जब कानून का डंडा चल रहा है, जब जेल की सलाखें सामने दिख रही हैं, तब जाकर जुगलबंदी हो रही है। इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भ्रष्टाचार के खिलाफ होने वाले एक्शन से बचने का ही है**

उन्होंने कहा कि आजकल एक नया शब्द बहुत पॉपुलर किया जा रहा है। वो शब्द है गारंटी। ये सारे विपक्षी दल भ्रष्टाचार और घोटालों की गारंटी हैं। कुछ दिन पहले इसका फोटो सेशन का कार्यक्रम हुआ था। इनमें शामिल होने वाले दलों को देखेंगे तो पता चलेगा कि वो सब मिलकर के कम से कम कुल 20 लाख करोड़ रुपये के घोटाले की गारंटी है। अकेले कांग्रेस का घोटाला ही लाखों-करोड़ों का है। 1.86 लाख करोड़ रुपये का कोयला घोटाला। 1.74 लाख करोड़ रुपये का टूजी घोटाला। 70 हजार करोड़ रुपये का कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला। 10 हजार करोड़ रुपये का मनरेगा घोटाला। हेलीकॉप्टर से लेकर सबमरीन तक कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां कांग्रेस के घोटाले का हाथ नहीं पहुंचा हो। आरजेडी पर हजारों करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप है। चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, पशुपालन शेड घोटाला, बाढ़ राहत घोटाला, आरजेडी के घोटालों की इतनी लंबी सूची है कि अदालतें भी थक गईं। एक के बाद एक सजा घोषित करती जा रही हैं। डीएमके पर अवैध तरीके से 1.25 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति बनाने का आरोप है। टीएमसी पर भी 23 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के घोटाले का आरोप हैं। रोज वैली घोटाला, शारदा घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटला, गो-तस्करी घोटाला, कोयला तस्करी घोटाला, बंगाल के लोग इन घोटालों को कभी भूल नहीं सकते हैं। एनसीपी पर करीब-करीब 70 हजार करोड़ रुपये के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। इन पार्टियों के घोटालों का मीटर कभी डाउन ही नहीं होता है। मैं तो कहूंगा कि भाजपा के किसी कार्यकर्ता को कोशिश करनी चाहिए कि इन पार्टियों का घोटाला मीटर बनाने की। आपलोग इनोवेटिव हो, एक बढ़िया घोटाला मीटर बना दीजिए। इन पार्टियों के पास घोटालों का ही अनुभव है।

विपक्ष पर जोरदार हमला करते हुए प्रधानमंत्रीजी ने कहा कि अगर इन विपक्षी पार्टियों की घोटाले की गारंटी है, तो मोदी की भी एक गारंटी है। मेरी गारंटी है कि हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। हर चोर-लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। जिसने गरीब को लूटा है, जिसने देश को लूटा है, उसका हिसाब होकर रहेगा। आज जब कानून का डंडा चल रहा है, जब जेल की सलाखें सामने दिख रही हैं, तब जाकर जुगलबंदी हो रही है। इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भ्रष्टाचार के खिलाफ होने वाले एक्शन से बचने का ही है।

श्री मोदी ने जनता से अपील करते हुए कहा कि आपको गांधी परिवार के बेटे-बेटी का विकास करना हो तो कांग्रेस को वोट दीजिए। आपको मुलायम सिंहजी के बेटे का भला करना है तो समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए। अगर आप लालू परिवार के बेटे-बेटियों का भला करना चाहते हो तो आरजेडी को वोट दीजिए। आपको शरद पवार की बेटी का भला करना हो तो एनसीपी को वोट दीजिए। आपको अब्दुल्ला परिवार के बेटे का भला करना हो तो नेशनल कांफ्रेंस को वोट दीजिए। आपको करुणानिधि के पोते-पोतियों का भला करना हो तो डीएमके को वोट दीजिए। आपको के चंद्रशेखर रावजी की बेटी का भला करना हो तो बीआरएस को वोट दीजिए। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको अपने बेटे, अपनी बेटी, अपने पोते-पोती, अपने नाती-नातिन और अपने परिवार के बच्चों का भला करना है तो वोट भाजपा को दीजिए।

महंगाई दर नियंत्रण में

राजस्थान से रचित कछवा ने प्रश्न पूछा कि हमारी सरकार की

गरीब कल्याण नीतियों के कारण लोगों को कई योजनाओं में बचत हो रही है। हम इसे कैसे लोगों तक लेकर जाएं। इसके उत्तर में प्रधानमंत्रीजी ने कहा कि आज भारत दुनिया के उन देशों में है जहां विकास बहुत तेज गति से हो रहा है और महंगाई दर नियंत्रण में है। कोरोना के बाद दुनिया के कितने ही देश ऐसे हैं जहां महंगाई में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पाकिस्तान में महंगाई दर 38% से ज्यादा है। श्रीलंका में 25% से ज्यादा है। बांग्लादेश में 10 प्रतिशत के आसपास है। भारत में ये 5% से भी कम है। कोरोना के खिलाफ इतने समय से चले आ रहे युद्ध के बावजूद भारत में हमने महंगाई को बेकाबू नहीं होने दिया।

किसान हो रहे हैं लाभान्वित

किसानों के लिए उठाये गए छत्तीसगढ़ से पार्टी कार्यकर्ता संजय सोढ़ी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में प्रधानमंत्रीजी ने कहा कि कांग्रेस की एक ही नीति थी— पहले किसानों को संकट में पड़ने दो और फिर कर्ज माफी के नाम पर झूठ बोलकर वोट की फसल काटो। 10 साल की सरकार में कांग्रेस ने एक बार कुछ हजार करोड़ रुपये की कर्ज माफी का ऐलान किया लेकिन असली किसानों तक यह लाभ पहुंचा ही नहीं। कर्ज माफी के नाम पर राजनीति करते थे कांग्रेस वाले। भाजपा सरकार पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा सीधे किसानों के बैंक खाते में भेज रही है। इससे छोटे से छोटा किसान भी लाभान्वित हो रहा है। अभी तक इसके तहत सवा दो लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में जमा हो चुके हैं। लगभग 11 करोड़ किसान इस योजना के लाभार्थी हैं। भाजपा की सरकार ने किसानों पर महंगे यूरिया, महंगे फर्टिलाइजर का भी बोझ नहीं पड़ने दिया। इसके लिए सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया, ताकि किसान को फर्टिलाइजर सस्ता मिले।

उन्होंने कहा कि भारत बीते 9 वर्षों में 10वें स्थान की अर्थव्यवस्था से पांचवें नंबर की आर्थिक ताकत बन गया है। इसका मतलब यह है कि बीते 9 वर्षों में भारत और भारतीयों की कमाई बढ़ी है, समृद्धि में हिस्सेदारी बढ़ी है।

हमारा उम्मीदवार एक ही है और वह है 'कमल'

प्रधानमंत्रीजी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सीट चाहे कोई भी हो, उम्मीदवार चाहे कोई भी हो, हमारा उम्मीदवार एक ही है और वह उम्मीदवार है कमल। कमल ही हमारा उम्मीदवार है। कमल से बड़ा कुछ नहीं है। हमारे लिए कमल ही सब कुछ है। जनता को यह भी लगे कि जहां कमल है, वहीं पर उसकी समस्याओं का हल भी है। आज जो यहां से ढाई हजार से ज्यादा कार्यकर्ता, हमारे अल्पकालीन विस्तारक, अलग-अलग राज्यों में जा रहे हैं, उन्हें भी इसका विशेष ध्यान रखना है। यह अभियान आपके लिए एक तपस्या से कम नहीं है। जिस गांव में आप जाएं, वहां के लोगों के साथ, वहां समाज के साथ उन्हीं की तरह जीवन जियें। न अलग रहें और न ही अलग दिखें।

श्री मोदी ने कहा कि मैं आज देश के प्रबुद्ध मतदाताओं का भी फिर से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आर्थिक हो या सामाजिक, देश आज निर्णायक फैसला इसलिए ले रहा है क्योंकि दशकों बाद देश ने एक मजबूत और स्थिर सरकार चुनी है। आज पूरी दुनिया में भारत को लेकर इतनी पॉजिटिविटी इसलिए है, क्योंकि यहां एक मजबूत सरकार है। आने वाले 25 साल यानी आजादी के अमृत काल में विकसित भारत के निर्माण के लिए यही स्थिरता, यही मजबूती हमारे लिए आवश्यक है। हमको इसे आगे बढ़ाना है। ■

अल्पकालिक विस्तारक संगठन की मजबूती के लिए काम करेंगे : जगत प्रकाश नड्डा

भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित 'मेरा बूथ, सबसे मजबूत' कार्यक्रम में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि जब पार्टी की बात आती है, तो प्रधानमंत्रीजी कभी भी हमें समय देने से मना नहीं करते। शासनिक एवं प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त रहने के बावजूद जब भी पार्टी को जरूरत होती है, प्रधानमंत्रीजी पार्टी के कार्यक्रम में उपस्थित होकर मार्गदर्शन देते हैं। उनकी कार्यपद्धति और मूल में संगठन रचा-बसा है। वे कुशल प्रशासक के साथ-साथ एक बहुत ही अच्छे संगठक भी हैं। प्रधानमंत्रीजी ने अपना जीवन संगठन में खपाते हुए बूथ पर काम किया और आज वे देश का नेतृत्व कर रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत और भारतीय जनता पार्टी को दुनिया में नई ऊंचाई पर स्थापित किया है। वे दिन-रात सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए समर्पित रहते हैं।

श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अल्पकालिक विस्तारक योजना का विचार पार्टी के संसदीय कार्यसमिति की बैठक में रखा था। उन्हीं के सुझावों पर अमल करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने 'मेरा बूथ, सबसे मजबूत' कार्यक्रम शुरू किया। इसके लिए एक चयनित प्रक्रिया के तहत देश भर से 6649 कार्यकर्ताओं को अल्पकालिक विस्तारक के रूप में चयनित कर प्रशिक्षित किया गया। ये विस्तारक अलग-अलग राज्यों में जाकर एक सप्ताह के लिए बूथ सशक्तीकरण के लिए काम करेंगे। प्रधानमंत्रीजी ने सुझाव दिया था कि कमजोर बूथ को मजबूत करने की जरूरत है। इसलिए पार्टी ने 100 लोकसभा और 50 विधानसभा का चयन किया] जहां ये विस्तारक संगठन की मजबूती के लिए काम करेंगे।

> सभी अल्पकालिक विस्तारक उमंग से भरे हुए हैं। आपलोग बूथों पर जाकर काम करें। वहां आपको कई बातें सीखने का अवसर मिलेगा और आप पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करेंगे

भारतीय जनता पार्टी के सशक्तीकरण में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के योगदान की चर्चा करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व एवं दिशा-निर्देशन में काम करते हुए भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई है। प्रधानमंत्रीजी ने ही ने सुझाव दिया था कि यदि भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है तो दुनिया के लोगों को पार्टी के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। उनके सुझाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने 'Know BJP' कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम के तहत अब तक दुनिया के दो प्रधानमंत्री, चार विदेश मंत्री और 60 राजदूत भारतीय जनता पार्टी के केन्द्रीय कार्यालय आये हैं और उन्होंने भाजपा को समझा है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की दूरदर्शिता और स्पष्ट नीतियों की वजह से बदलते भारत की तस्वीर का खाका खींचते हुए श्री नड्डा ने कहा कि आज दुनिया में भारत को ब्राइट स्पॉट की तरह देखा जा रहा है। दुनिया को भारत की अर्थव्यवस्था में आशा की किरणें देखने को मिल रही है। नौ साल पहले भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में दसवें स्थान पर खड़ी थी और आज भारत ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया में पांचवीं आर्थिक महाशक्ति बन गया है। सारी अंतरराष्ट्रीय आर्थिक रेटिंग एजेंसियां मानती हैं कि भारत दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी देश गांव, गरीब, किसान, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, पिछड़े, आदिवासी, युवा एवं महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए कटिबद्ध भाव से निरंतर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ से अधिक गरीबों को घर दिया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को हर महीने प्रति व्यक्ति पांच किलो अनाज मुफ्त दिया जा रहा है। उज्ज्वला योजना में साढ़े 9 करोड़ माताओं-बहनों को गैस कनेक्शन दिया गया। 'आयुष्मान भारत योजना' के तहत लगभग 55 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा दी जा रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लगभग 11 करोड़ किसानों को प्रति वर्ष 6-6 हजार रुपए दिया जा रहा है।

अल्पकालिक विस्तारकों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए श्री नड्डा ने कहा कि "सभी अल्पकालिक विस्तारक उमंग से भरे हुए हैं। आपलोग बूथों पर जाकर काम करें। वहां आपको कई बातें सीखने का अवसर मिलेगा और आप पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करेंगे।" ■

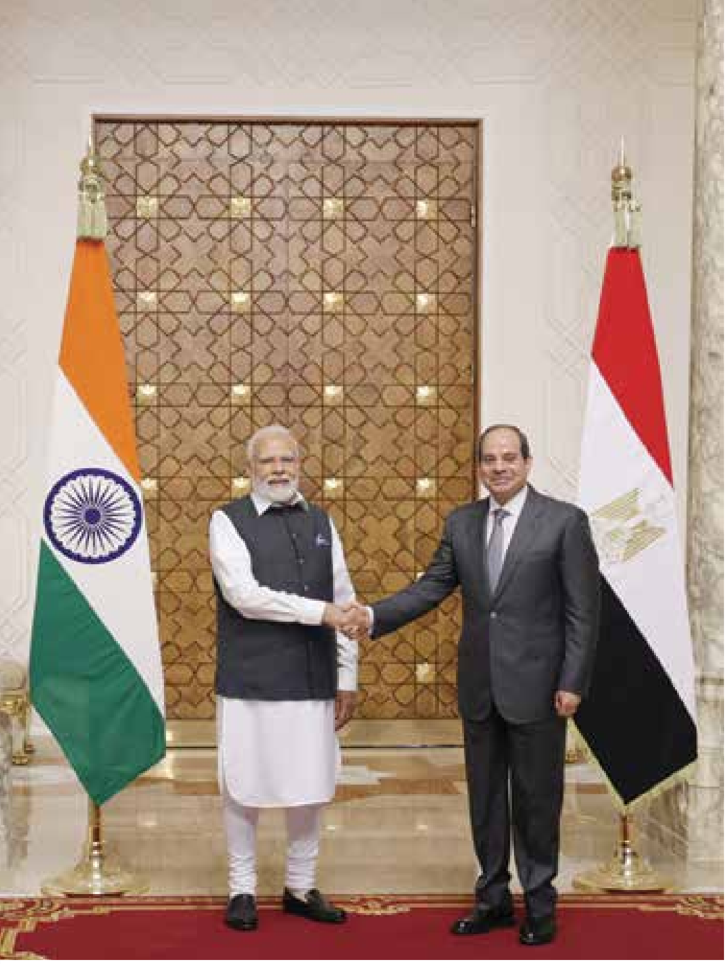

भारत और मिस्र ने 'रणनीतिक साझेदारी' पर किए हस्ताक्षर

अमेरिका की अत्यंत सफल राजकीय यात्रा के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी मिस्र के राष्ट्रपति श्री अब्देल फतह अल-सिसी के निमंत्रण पर 24 जून को मिस्र पहुंचे। प्रधानमंत्री की यह पहली मिस्र यात्रा थी। हवाई अड्डे पर मिस्र के प्रधानमंत्री ने श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया तथा वहीं पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री श्री मोदी और राष्ट्रपति श्री सिसी ने द्विपक्षीय संबंधों को 'रणनीतिक साझेदारी' तक बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस यात्रा के दौरान कृषि, पुरातत्व एवं पुरावशेष और प्रतिस्पर्धा कानून के क्षेत्र में तीन समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए गए

मिस्र के राष्ट्रपति से मुलाकात

अरब गणराज्य मिस्र के राष्ट्रपति श्री अब्देल फतह अल-सिसी ने 25 जून, 2023 को अल-इत्तिहादिया पैलेस में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अगवानी की। दोनों नेताओं ने जनवरी, 2023 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति श्री सिसी की राजकीय यात्रा को स्नेहपूर्वक याद किया और इससे द्विपक्षीय संबंधों को मिली गति का स्वागत किया। उन्होंने इस बात पर भी सहमति प्रकट की कि मिस्र की कैबिनेट में नव गठित 'इंडिया यूनिट' द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की दिशा में कारगर है।

दोनों नेताओं ने भारत और मिस्र के बीच विशेष रूप से व्यापार और निवेश, सूचना प्रौद्योगिकी, रक्षा और सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य, संस्कृति और लोगों के बीच पारस्परिक संबंधों जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने के तरीकों के बारे में चर्चा की।

प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति श्री सिसी ने खाद्य व ऊर्जा असुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल साउथ के लिए मिलकर आवाज उठाने की आवश्यकता जैसे मुद्दों को रेखांकित करते हुए जी-20 में सहयोग बढ़ाने के बारे में भी चर्चा की। प्रधानमंत्री ने सितंबर, 2023 में नई दिल्ली में आयोजित होने वाले जी-20 देशों के नेताओं के शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति श्री सिसी का स्वागत करने के प्रति उत्सुकता प्रकट की।

दोनों नेताओं द्वारा द्विपक्षीय संबंधों को 'रणनीतिक साझेदारी' तक बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। कृषि, पुरातत्व एवं पुरावशेष और प्रतिस्पर्धा कानून के क्षेत्र में तीन समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए गए।

इस अवसर पर मिस्र के प्रधानमंत्री श्री मुस्तफा मैडबौली और उनकी कैबिनेट के कई अन्य वरिष्ठ मंत्री भी उपस्थित थे। भारत की ओर से विदेश मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

मिस्र के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मिस्र के मंत्रिमंडल की 'भारत इकाई' के साथ बैठक

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मिस्र की राजकीय यात्रा पर काहिरा पहुंचने के तुरंत बाद 24 जून को मिस्र के मंत्रिमंडल की 'भारत इकाई' के साथ एक बैठक की। इस 'भारत इकाई' की स्थापना इस वर्ष की शुरुआत में मिस्र के राष्ट्रपति श्री अब्देल फतह अल-सिसी की गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि के रूप में भारत की राजकीय यात्रा के बाद की गई थी। इस 'भारत इकाई' की अध्यक्षता मिस्र के प्रधानमंत्री श्री मुस्तफा मैडबौली करते हैं तथा इसमें कई मंत्री एवं वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं।

प्रधानमंत्री श्री मैडबौली और मंत्रिमंडल के उनके सहयोगियों ने 'भारत इकाई' की विभिन्न गतिविधियों की रूपरेखा प्रस्तुत की और सहयोग के नए क्षेत्रों का प्रस्ताव रखा। उन्होंने अपने भारतीय समकक्षों की ओर से प्राप्त सकारात्मक प्रतिक्रिया की सराहना की और विभिन्न क्षेत्रों में भारत-मिस्र द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के प्रति उत्सुकता जताई।

प्रधानमंत्री को मिस्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार 'ऑर्डर ऑफ द नाइल' से किया गया सम्मानित

मिस्र के राष्ट्रपति श्री अब्देल फतह अल-सिसी ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को 25 जून, 2023 को काहिरा की प्रेसीडेंसी में आयोजित एक विशेष समारोह में मिस्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार 'ऑर्डर ऑफ द नाइल' से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री ने इस सम्मान के लिए भारत के लोगों की ओर से राष्ट्रपति श्री सिसी को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को मिस्र का सर्वोच्च राजकीय सम्मान मिलने की प्रशंसा की। अपने ट्वीट में श्री अमित शाह ने कहा कि वैश्विक आभा वाले राजनेता के रूप में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की शानदार सफलता को एक और सम्मान प्राप्त हुआ है जब मिस्र ने मोदी जी को अपना सर्वोच्च राजकीय सम्मान, 'द ऑर्डर ऑफ नाइल अवार्ड' प्रदान किया है। श्री नरेन्द्र मोदी जी एकमात्र ऐसे भारतीय प्रधानमंत्री हैं, जिन्हें सबसे अधिक देशों द्वारा ऐसे सम्मान प्रदान किए गए हैं।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने 'भारत इकाई' की स्थापना की सराहना की और भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए इस 'संपूर्ण सरकार वाले दृष्टिकोण' का स्वागत किया। उन्होंने आपसी हित के विभिन्न क्षेत्रों में मिस्र के साथ मिलकर काम करने की भारत की तत्परता को साझा किया।

बैठक में व्यापार एवं निवेश, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, आईटी, डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म, दवाओं और दोनों देशों के लोगों के बीच परस्पर संबंध जैसे क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री श्री मैडबौली के अलावा इस बैठक में मिस्र के सात कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

प्रधानमंत्री काहिरा में अल-हकीम मस्जिद गए

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी मिस्र की राजकीय यात्रा के दौरान 25 जून को काहिरा में अल-हकीम मस्जिद गए। मिस्र के पर्यटन और पुरावशेष मंत्री डॉ. मुस्तफा वज़ीरी ने प्रधानमंत्री की अगवानी की। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने बोहरा समुदाय के नेताओं से भी मुलाकात की, जो इस फातिमीद युग की शिया मस्जिद के रख-रखाव में सक्रिय रूप से शामिल हैं। उन्होंने भारत और मिस्र के लोगों के बीच प्रगाढ़ संबंधों पर प्रकाश डाला।

श्री मोदी ने 24 जून को मिस्र के ग्रैंड मुफ्ती डॉ. शॉकी इब्राहिम अल्लम से भी मुलाकात की। ग्रैंड मुफ्ती ने हाल की अपनी भारत यात्रा को गर्मजोशी से याद किया और भारत एवं मिस्र के बीच मजबूत सांस्कृतिक संबंधों तथा दोनों देशों के लोगों के बीच के पारस्परिक संबंधों पर प्रकाश डाला। ग्रैंड मुफ्ती ने समावेशिता और बहुलतावाद को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री के नेतृत्व की सराहना भी की।

चर्चा के केन्द्र में समाज में सामाजिक एवं धार्मिक सद्भाव और उग्रवाद एवं कट्टरपंथ से निपटने से जुड़े मुद्दे भी रहे। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत मिस्र के सामाजिक न्याय मंत्रालय के अधीन दार-अल-इफ्ता में आईटी से संबंधित एक उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित करेगा।

प्रधानमंत्री ने हेलियोपोलिस युद्ध स्मारक का किया दौरा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने काहिरा में हेलियोपोलिस कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव सेमेटरी का दौरा किया। श्री मोदी ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मिस्र और अदन में अपनी जान न्योछावर करने वाले 4300 से अधिक बहादुर भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

मिस्र में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 24 जून को काहिरा में भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत की। भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ अपनी बातचीत में श्री मोदी ने भारत-मिस्र संबंधों को मजबूत करने में योगदान देने के लिए इस समुदाय की सराहना की। इस कार्यक्रम में छात्रों, पेशेवरों और व्यावसायियों सहित प्रवासी भारतीय समुदाय ने भारी संख्या में भाग लिया। ■

भूपेश बघेल सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है : जगत प्रकाश नड्डा

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 30 जून, 2023 को बिलासपुर, छत्तीसगढ़ के नॉर्थ ईस्ट रेलवे इंस्टीट्यूट, फुटबॉल मैदान में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार के 9 सफल वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित किया। कार्यक्रम में भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री अरुण साव, केंद्र सरकार में मंत्री श्रीमती रेणुका सिंह, छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष श्री नारायण चंदेल एवं प्रदेश के प्रभारी श्री ओम प्रकाश माथुर सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित थे।

भारत की बदलती तस्वीर

कांग्रेस पर हमले की शुरुआत करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि कांग्रेस के नेता कहते हैं कि देश आत्मनिर्भर कहां हुआ? अरे भाई, देश तो आत्मनिर्भर हुआ लेकिन आपके भ्रष्टाचार पर रोक लग गई है। पहले देश में किसी भी बीमारी का टीका आने में वर्षों लग जाते थे लेकिन कोरोना काल में देश में केवल 9 महीने में दो-दो स्वदेशी कोविड-रोधी टीके विकसित हुए और 220 करोड़ वैक्सीनेशन हुए। ये आत्मनिर्भर भारत की कहानी ही तो है। विगत 9 वर्षों में आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने के लिए 18 लाख करोड़ रुपये खर्च किये गए हैं। इस साल आधारभूत संचना के विकास पर 10 लाख करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया है। 2014 से पहले औसतन 12 किमी नेशनल हाइवे प्रतिदिन बनता था जबकि आज लगभग 29 किमी नेशनल हाइवे प्रतिदिन बन रहा है। देश में लगभग 54 हजार किलोमीटर नेशनल हाइवे बना है, सैकड़ों किमी मेट्रो रेल बना है। 2014 में रेल की पटरी औसतन 5.6 किलोमीटर प्रतिदिन बिछायी जाती थी, वहीं आज 14.3 किलोमीटर प्रतिदिन बिछायी जा रही है। 2014 से पहले आजादी के 70 साल में 74 एयरपोर्ट बने थे जबकि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नौ साल में 74 नए एयरपोर्ट बनाए। 23 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। छत्तीसगढ़ को भी वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी गई है। लगभग 3.28 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनी हैं। यह भारत की बदलती तस्वीर है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गांव, गरीब, किसान, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, पिछड़े, आदिवासी, युवा एवं महिलाओं का सशक्तीकरण किया है। छत्तीसगढ़ में लगभग 2 करोड़ लोगों को पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ मिल रहा है। इसके कारण देश में गरीबी 22 प्रतिशत से घटकर 10 प्रतिशत के नीचे आ गई है और अति गरीबी की दर भी एक प्रतिशत से नीचे बनी हुई है। पीएम आवास योजना के तहत छत्तीसगढ़ में लगभग 14.80 लाख मकान बने हैं। स्वच्छ भारत अभियान के तहत प्रदेश में लगभग 34.5 लाख इज्जत घर बने हैं। उज्ज्वला योजना के तहत छत्तीसगढ़ में 33 लाख बहनों को गैस कनेक्शन दिया गया है। आयुष्मान भारत के तहत राज्य में लगभग 36.5 लाख परिवारों को लाभ हो रहा है, जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश में लगभग 22 लाख घरों में नल से जल पहुंच रहा है और पीएम किसान सम्मान निधि के तहत राज्य में लगभग 27 लाख किसानों को फायदा हो रहा है।

उन्होंने कहा कि रायपुर में एम्स भाजपा की सरकार ने दिया था। बिलासपुर में सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक दिया। भिलाई में आईआईटी दी है, छत्तीसगढ़ में शत-प्रतिशत रेलवे का विद्युतीकरण हो रहा है, पीएम ग्रामीण सड़क योजना के तहत कई किलोमीटर सड़क बनी है। 464 किलोमीटर का रायपुर-विशाखापत्तनम इकोनॉमिक कॉरिडोर बना है। पीएम गतिशक्ति योजना के तहत अंबिकापुर, जगदलपुर और बिलासपुर में एयरपोर्ट का अपग्रेडेशन हो रहा है।

भ्रष्टाचारी कांग्रेस सरकार

भूपेश बघेल सरकार को घोटालों की सरकार बताते हुए श्री नड्डा ने कहा कि भूपेश बघेल की सरकार में कोयला घोटाला हुआ है, कोयला माफिया हावी है। भूपेश बघेल की डिप्टी सेक्रेटरी जेल में हैं। अवैध खनन घोटाला हो रहा है। हजारों टन चावल मार्केट से गायब हो गया। राजा बोलता है दुकानदार को पकड़ूंगा। अरे उनको तो पकड़ो जो काले कारनामें कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हजारों करोड़ रुपये का शराब घोटाला हुआ है। लैंड घोटाला हो रहा है। ऐसी भ्रष्टाचारी कांग्रेस सरकार को घर बिठाइये और गरीबों का कल्याण करनेवाली और छत्तीसगढ़ को विकास के रास्ते पर ले जाने वाली भारतीय जनता पार्टी को सेवा का मौका दीजिये। ■

'कांग्रेस सरकार ने राजस्थान को भ्रष्टाचार में नंबर वन बना दिया है'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 29 जून, 2023 को काली बगीची, भरतपुर स्थित पार्टी के नवीन जिला कार्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने यहीं से जैसलमेर जिला भाजपा कार्यालय का वर्चुअल उद्घाटन और बाड़मेर जिला भाजपा कार्यालय का वर्चुअल शिलान्यास किया। इसके पश्चात् उन्होंने पार्टी के राष्ट्रव्यापी अभियान 'संपर्क से समर्थन' के तहत बघेरा कला, भरतपुर में 'अपना घर' संस्थान के संस्थापक डॉ. बी एम भारद्वाज के घर जाकर उनसे मुलाक़ात की और श्री नरेन्द्र मोदी सरकार के 9 वर्ष की उपलब्धियों की बुकलेट भी सौंपी। इसके पश्चात् उन्होंने कृषि ऊपज मंडी, भरतपुर में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। कार्यक्रम में राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं सांसद श्री सीपी जोशी, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं राजस्थान के भाजपा प्रभारी श्री अरुण सिंह, केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत एवं नेता प्रतिपक्ष राजस्थान श्री राजेंद्र सिंह राठौड़ सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता एवं पार्टी पदाधिकारी उपस्थित थे।

काली बगीची, राजस्थान

भरतपुर जिला भाजपा कार्यालय का उद्घाटन करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि राजस्थान में 15 जिला भाजपा कार्यालय काम करना शुरू कर चुके हैं और पांच कार्यालय शीघ्र ही समर्पित होंगे। कार्यालय हमारे लिए संस्कार केंद्र की तरह है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की नीतियों एवं गरीब कल्याण योजनाओं के बल पर देश के गांव, गरीब, किसान, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, पिछड़े, आदिवासी, युवा एवं महिलाओं का सशक्तीकरण हो रहा है।

कांग्रेस की सरकार पर हमला जारी रखते हुए श्री नड्डा ने कहा कि भरतपुर जिले के रहने वाले गहलोत सरकार के एक मंत्री का पति दुष्कर्म के केस में फंसा है। गहलोत सरकार उसे बचाने की पूरी कोशिश की है। कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान को भ्रष्टाचार में नंबर वन बना दिया है। राजस्थान में महिलायें कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। विकास के लिए राजस्थान में भी कमल खिलाने की जरूरत है। ■

छत्तीसगढ़ सरकार वामपंथी उग्रवाद को लेकर गंभीर नहीं है: राजनाथ सिंह

रक्षा मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार प्रदेश में वामपंथी उग्रवाद को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। श्री सिंह ने कहा कि तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा अलग छत्तीसगढ़ राज्य बनाने का निर्णय आदिवासी समुदायों के कल्याण और उन्हें उनके उचित अधिकार दिलाने जैसे मुद्दों को ध्यान में रखकर किया गया था।

01 जुलाई, 2023 को आदिवासी बहुल कांकेर, छत्तीसगढ़ में एक विशाल सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के गतिशील नेतृत्व में एनडीए सरकार ने पिछले नौ वर्षों में वामपंथी उग्रवाद पर सफलतापूर्वक अंकुश लगाया है और अब माओवादी समस्या देश के कुछ राज्यों तक ही सीमित है।

कांकेर, छत्तीसगढ़

श्री राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा आदिवासियों की हितैषी रही है, जबकि कांग्रेस ने आदिवासियों के विकास के लिए कुछ भी किए बिना कई वर्षों तक देश पर शासन किया।

उन्होंने पूछा, "क्या आपने कभी सोचा था कि आदिवासी समुदाय की एक बेटी सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंच कर भारत की राष्ट्रपति बन सकती है?"

भारत के इतिहास में पहली बार मोदी सरकार ने आदिवासी समुदायों के विकास के लिए 90,000 करोड़ रुपये का अलग बजटीय आवंटन किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस शासन के दौरान जबरन और गलत तरीके से धर्मांतरण हो रहा था।

अपने कांकेर दौरे के दौरान रक्षा मंत्री ने भाजपा द्वारा आयोजित 'संपर्क से समर्थन अभियान' के तहत प्रसिद्ध शिल्पकार पद्मश्री अजय कुमार मंडावी से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। ■

कांग्रेस की इस 3'D' वाली सरकार को उखाड़ फेंकना है : अमित शाह

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 30 जून, 2023 को उदयपुर, राजस्थान के गांधी मैदान में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार के सफल 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित किया। कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री सीपी जोशी, पूर्व मुख्यमंत्री एवं पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया, केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री एवं राजस्थान के भाजपा प्रभारी श्री अरुण सिंह सहित पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित थे।

श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में बीते 9 साल कई मायनों में परिवर्तनकारी रहे हैं। राजस्थान में पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ लगभग 80 लाख किसानों को मिल रहा है। राजस्थान में किसानों के एकाउंट में लगभग 16,000 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। 'जल जीवन मिशन' के तहत प्रदेश में लगभग 43 लाख परिवारों को नल से जल मिल रहा है। राजस्थान में लगभग 86 लाख शौचालय बने हैं और लगभग 4.2 करोड़ लोगों को 'गरीब कल्याण अन्न योजना' के तहत मुफ्त अनाज मिल रहा है। लगभग 5.75 करोड़ उज्ज्वला कनेक्शन वितरित किये गए हैं जिसमें से लगभग 84 हजार ट्राइबल कनेक्शन हैं। प्रदेश में पीएम आवास योजना के तहत लगभग 18 लाख लोगों को घर मिला है।

उदयपुर, राजस्थान

उन्होंने कहा कि मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, कांग्रेस की गहलोत सरकार पिछले 3-4 साल से लगातार देश भर में भ्रष्टाचार के सर्वेक्षण में, भ्रष्टाचार करने में नंबर एक है। खनन विभाग में लगभग 66,000 करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार हुआ। उदयसागर झील के नाम पर 2,000 करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार हुआ। प्रतापगढ़ में लगभग 1,000 करोड़ रुपये का लाइमस्टोन खान का भ्रष्टाचार हुआ। राजस्थान सचिवालय में अफसरों के आलमीरा में से दो करोड़ रुपये और एक किलो सोना निकलता है। काली सिंह बांध में करोड़ों रुपये का घोटाला हुआ। गरीबों के राशन में लगभग 100 करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार हुआ और वृद्धावस्था पेंशन के नाम पर भी ये लोग लगभग 450 करोड़ रुपये खा गए।

श्री शाह ने कहा कि कांग्रेस की गहलोत सरकार 3'D' से घिरी हुई सरकार है। 3D का मतलब है— दंगा, महिलाओं से दुर्व्यवहार और दलितों पर अत्याचार। कांग्रेस की इस 3'D' वाली सरकार को उखाड़ फेंकना है। ■

'मोदी सरकार में पिछड़े समाज के लोगों का जीवन ऊपर उठा है'

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 2 जुलाई, 2023 को लखनऊ, उत्तर प्रदेश के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में डॉ. सोनेलाल पटेल जी की 74वीं जयंती के उपलक्ष्य में 'जन-स्वाभिमान दिवस' कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि डॉ. सोनेलाल पटेल जी के जीवन से राजनीतिक और सामाजिक जीवन में काम कर रहे लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती अनुप्रिया पटेल, केंद्रीय मंत्री श्री रामदास आठवले, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री चौधरी भूपेंद्र सिंह, उप-मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य, उप-मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक सहित राज्य सरकार में कई मंत्री और भाजपा एवं अपना दल के नेता उपस्थित थे।

श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में बीते 9 साल में देश के लगभग 60 करोड़ गरीबों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, दलितों और पिछड़े समाज के लोगों के जीवन को ऊपर उठाने काम हुआ है। आजादी के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में यह पहली मंत्रिपरिषद् है जिसमें पिछड़े समाज से लगभग 27 प्रतिशत मंत्री बने हैं। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी कई बार गठबंधन में सत्ता में रही, लेकिन कभी भी पिछड़े वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता नहीं दी। उन लोगों ने कभी भी दलित और आदिवासी आयोग की तरह पिछड़ा वर्ग आयोग नहीं बनाया। ये प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी हैं, जिन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता दी, जिससे पिछड़ा समाज के कल्याण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने एमबीबीएस और एमडी की प्रवेश परीक्षा में पिछड़ा समाज के लिए 27 प्रतिशत का आरक्षण का प्रावधान किया है। ओबीसी छात्रों का ट्यूशन फी भी माफ़ किया गया है। नीट परीक्षा में आरक्षण दिया गया है। पेट्रोल एवं गैस एजेंसियों में भी ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। ओबीसी की प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक सहायता के लिए अनुदान राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके खाते में दिया गया। ओबीसी समाज के उद्यमियों के लिए वेंचर कैपिटल का बनाया गया है।

लखनऊ, उत्तर प्रदेश

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने आजमगढ़ मे महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय की स्थापना की। डॉ. सोनेलाल जी के नाम से प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। ■

'पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना ने देश की तस्वीर बदली है'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 30 जून, 2023 को खरगौन, मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध मेला मैदान में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार के 9 सफल वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित किया। श्री नड्डा ने सरदार वल्लभभाई पटेल चौराहा से सभास्थल तक खुली जीप से भव्य रोड शो भी किया। रोड शो में उनके साथ मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित थे।

श्री नड्डा ने कहा कि श्री नरेन्द्र मोदी सरकार और उनके नेतृत्व में चलने वाली राज्य सरकार प्रो-रिस्पॉन्सिबल, प्रो-रिस्पॉन्सिव और प्रो-एक्टिव सरकार है। पीएम ग्राम सड़क योजना में लगभग 3.28 लाख किमी सड़कें बनी हैं। मध्य प्रदेश में 51 लाख लोगों को गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ मिल रहा है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना ने देश की तस्वीर बदली है। इसके बल पर देश में गरीबी 22 प्रतिशत से घटकर 10 प्रतिशत के नीचे आ गई है और देश में अति गरीबी भी एक

खरगौन, मध्य प्रदेश

प्रतिशत से नीचे बनी हुई है। इस योजना से राजस्थान के लगभग 4.40 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है। मॉर्गन स्टेनली ने भारत को आर्थिक दृष्टि से दुनिया का ब्राइट स्पॉट कहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे मजबूत है। पीएम आवास योजना, पीएम किसान सम्मान निधि, जल जीवन मिशन, उज्ज्वला योजना, जन-धन योजना, सौभाग्य योजना, आयुष्मान भारत योजना जैसी योजनाओं ने लोगों के जीवन-स्तर को ऊपर उठाया है। मध्य प्रदेश में लगभग 83.50 लाख परिवारों को आयुष्मान भारत की सुविधा मिल रही है। मध्य प्रदेश में 73 लाख इज्जत घर दिए गए। इन सभी योजनाओं को लाभ पात्रता के आधार पर दिया जा रहा न कि जाति-पंथ के आधार पर। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग 4 करोड़ लोगों को पक्के मकान दिए गए। मध्य प्रदेश में 38 लाख आवास बन चुके हैं और 7 लाख आवास की स्वीकृति दे दी गयी है। जब कमलनाथ की सरकार थी और विकास को अवरुद्ध कर दिया गया था, तब कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में बननेवाले 1.28 लाख घर को वापस केंद्र भेज दिया था। क्या कमल नाथ गरीब बहनों का अपराधी है या नहीं? ऐसे लोगों को सत्ता में वापस नहीं आना चाहिए। ■

'भ्रष्टाचारियों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए राज्य की सभी सीटों पर कमल खिलाइये'

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 29 जून, 2023 को बिहार के लखीसराय में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार के सफल 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित किया। कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ संजय जायसवाल, पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं सांसद श्री सुशील मोदी सहित पार्टी के अनेक वरिष्ठ नेता उपस्थित थे।

बिहार में श्री नरेन्द्र मोदी सरकार के विकास कार्यों को रेखांकित करते हुए श्री शाह ने कहा कि मुंगेर से बेगूसराय तक रेल सड़क को डबल और पुल के निर्माण का काम हुआ है, मुंगेर में इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित हुआ है, मुंगेर में मेडिकल कॉलेज बनाया गया, रोडवेज के लिए लगभग तीन लाख करोड़ रुपये के 13 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे दिए गए, भारतमाला के तहत लगभग 45,000 करोड़ रुपये दिए गए, बिहार-झारखंड एक्सप्रेस-वे के लिए लगभग 28,500 करोड़ रुपये

लखीसराय, बिहार

दिए गए, 6,800 करोड़ रुपये की लागत से गंगा पर पुल और सड़क उन्नयन को मंजूरी दी गई है। लगभग 3400 करोड़ रुपये की लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना लागू की गई है, लगभग 230 किमी लंबा असम-दरभंगा हाइवे का काम चल रहा है, 175 करोड़ रुपये की लागत से मधुबनी में पीएम सड़क योजना का काम चल रहा है। रेलवे ट्रैक पर 85 नए ओवरब्रिज और विद्युतीकरण का काम हो रहा है। नीतीश बाबू, आप जवाब दीजिये, आपने क्या किया?

विपक्ष पर हमला जारी रखते हुए श्री शाह ने कहा कि हमने पटना में भाजपा विरोधी दलों का एक बड़ा फोटो सेशन देखा। ये वो पार्टियां हैं जिनके ऊपर 2004 से 2014 के कालखंड के दौरान लगभग 20 लाख करोड़ रुपये के घपले-घोटाले और भ्रष्टाचार के आरोप हैं। आपको शर्म आनी चाहिए नीतीश बाबू कि आप 20 लाख करोड़ रुपये के घपले-घोटाले वाली कांग्रेस, आरजेडी, तृणमूल, एनसीपी, डीएमके और अरविंद केजरीवाल के साथ बैठकर सत्ता हथियाने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री शाह ने कहा कि बिहार को जंगलराज से मुक्त करने के लिए और भ्रष्टाचार करने वालों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए बिहार में सभी की सभी सीटों पर कमल खिलाइये। ■

संगठनात्मक नियुक्तियां

आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड और पंजाब में नए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नियुक्त

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 4 जुलाई, 2023 को आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड और पंजाब के नए प्रदेश भाजपा अध्यक्षों की नियुक्ति की।

पार्टी की एक विज्ञप्ति के अनुसार भाजपा की राष्ट्रीय महामंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमती डी. पुरंदेश्वरी को भाजपा, आंध्र प्रदेश का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

इसी तरह, केंद्रीय मंत्री श्री जी किशन रेड्डी को भाजपा, तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है।

झारखंड भाजपा विधायक दल के नेता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी को झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष का दायित्व दिया गया है।

इसी प्रकार पूर्व सांसद श्री सुनील कुमार जाखड़ को भाजपा, पंजाब प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ■

राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश और तेलंगाना के लिए नए चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 07 जुलाई, 2013 को राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश और तेलंगाना जैसे चुनावी प्रदेशों के लिए चुनाव प्रभारियों और सह-प्रभारियों की नियुक्ति की।

पार्टी की एक विज्ञप्ति के अनुसार केंद्रीय मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी राजस्थान के चुनाव प्रभारी होंगे, जबकि श्री नितिन पटेल और श्री कुलदीप बिश्नोई सह प्रभारी होंगे।

छत्तीसगढ़ में श्री ओम प्रकाश माथुर पार्टी के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री श्री मनसुख मंडाविया सह प्रभारी होंगे।

केंद्रीय मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव को मध्यप्रदेश प्रभारी का दायित्व दिया गया है। केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव प्रदेश के सह प्रभारी होंगे।

पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर को तेलंगाना का चुनाव प्रभारी बनाया गया है और भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री श्री सुनील बंसल प्रदेश के सह प्रभारी होंगे। ■

अन्य नियुक्तियां

भाजपा द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री किरण कुमार रेड्डी को भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है।

विधायक और तेलंगाना के पूर्व वित्त मंत्री श्री ईटेला राजेंदर को आगामी तेलंगाना विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा की प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

05 जुलाई 2023 को पार्टी की एक अन्य विज्ञप्ति में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने तेलंगाना के पूर्व सांसद श्री कोमाटिरेड्डी राज गोपाल रेड्डी को भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया। ■

भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के नये सदस्य नियुक्त

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 8 जुलाई, 2023 को पार्टी के 10 वरिष्ठ नेताओं को भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य के रूप में नियुक्त किया। पार्टी की एक विज्ञप्ति के अनुसार राष्ट्रीय कार्यकारिणी के नए सदस्यों के नाम निम्न हैं:

श्री सुरेश कश्यप
डॉ. संजय जायसवाल
श्री विष्णु देव साय
श्री धरमलाल कौशिक
श्री अश्वनी शर्मा
श्री बंदी संजय कुमार
श्री सोमू वीरराजू
श्री दीपक प्रकाश
श्री किरोड़ी लाल मीणा
डॉ. सतीश पूनिया ■

भाजपा केरल प्रदेश महामंत्री (संगठन) नियुक्त

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 08 जुलाई, 2023 को श्री सुभाष कन्नोथ को केरल भाजपा का नया प्रदेश महामंत्री (संगठन) नियुक्त किया। यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। ■

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने विदेशी मिशनों के राजनयिक प्रमुखों से मुलाकात की

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 05 जुलाई, 2023 को नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में ‘भाजपा को जानें’ पहल के तहत भारत में विदेशी मिशनों के राजनयिक प्रमुखों से मुलाकात की।

इस बैठक के बाद श्री नड्डा ने एक ट्वीट में कहा, “भाजपा को जानो’ पहल के हिस्से के रूप में भाजपा मुख्यालय में विभिन्न देशों के मिशनों के प्रमुखों के साथ बातचीत करना खुशी की बात थी। इस पहल के माध्यम से हमारा लक्ष्य अपनी पार्टी की विचारधारा और दृष्टिकोण को वैश्विक मंचों पर साझा करना और उन्हें भारत की प्रगति में हमारे योगदान के बारे में सूचित करना है।”

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बांग्लादेश, मिस्र, जर्मनी, ग्रीस, गुयाना, लेबनान, मलेशिया, मोजाम्बिक, दक्षिण कोरिया, सूरीनाम, स्वीडन और तंजानिया के राजनयिकों से बातचीत की।

इस बैठक के दौरान श्री नड्डा ने घोषणा की कि भाजपा इस साल दक्षिण अफ्रीका में अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा आयोजित किए जाने वाले ‘ब्रिक्स राजनीतिक दल प्लस संवाद’ सम्मेलन में भाग लेगी।

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह भी घोषणा की कि बांग्लादेश की सत्तारूढ़ पार्टी अवामी लीग और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (माओवादी सेंटर) का प्रतिनिधिमंडल निकट भविष्य में भाजपा के निमंत्रण पर भारत का दौरा करेगा।

श्री नड्डा ने विदेशी राजनयिकों को पार्टी के इतिहास, संघर्ष, सफलता, विचारधारा और राष्ट्र निर्माण में योगदान के बारे में भी जानकारी दी।

उन्होंने भाजपा की ‘अभूतपूर्व’ वृद्धि, पार्टी के सदस्यता अभियान और प्रौद्योगिकी के उपयोग के साथ-साथ विभिन्न प्रदेशों में पार्टी की उपस्थिति बढ़ाने की रणनीति के बारे में पूछे गए सवालों का भी विस्तार से जवाब दिया।

बैठक के दौरान पार्टी के विदेश विभाग के प्रभारी श्री विजय चौथाईवाले, पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी श्री अनिल बलूनी और अन्य नेता भी उपस्थित थे। ■

‘संपर्क से समर्थन’ अभियान

छत्तीसगढ़ में 30 जून, 2023 को ‘संपर्क से समर्थन’ अभियान के तहत संत श्री साईं लालदास जी से मुलाकात करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा

पेट्टा (तिरुवनंतपुरम) में 26 जून, 2023 को पार्टी के ‘संपर्क से समर्थन’ अभियान के तहत ‘केरल कौमुदी’ के प्रधान संपादक श्री दीपू रवि से मुलाकात करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा

किसानों के लिए 3,70,128.7 करोड़ रुपये की नवीन योजनाओं को मिली मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने 28 जून को 3,70,128.7 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ किसानों के लिए नवीन योजनाओं के एक विशेष पैकेज को मंजूरी दी। योजनाओं का समूह टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देकर किसानों के समग्र कल्याण और उनकी आर्थिक बेहतरी पर केंद्रित है। ये पहल किसानों की आय बढ़ायेंगी, प्राकृतिक एवं जैविक खेती को मजबूती देंगी, मिट्टी की उत्पादकता को पुनर्जीवित करेंगी और साथ ही खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित करेंगी।

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने किसानों को करों और नीम कोटिंग शुल्कों को छोड़कर 242 रुपये प्रति 45 किलोग्राम की बोरी की समान कीमत पर यूरिया की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए यूरिया सब्सिडी योजना को जारी रखने की मंजूरी दे दी। पैकेज में तीन वर्षों के लिए (2022-23 से 2024-25) यूरिया सब्सिडी को लेकर 3,68,676.7 करोड़ रुपये आवंटित करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। यह पैकेज हाल ही में अनुमोदित 2023-24 के खरीफ मौसम के लिए 38,000 करोड़ रुपये की पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) के अतिरिक्त है।

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने किसानों को करों और नीम कोटिंग शुल्कों को छोड़कर 242 रुपये प्रति 45 किलोग्राम की बोरी की समान कीमत पर यूरिया की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए यूरिया सब्सिडी योजना को जारी रखने की मंजूरी दे दी

किसानों को यूरिया की खरीद के लिए अतिरिक्त खर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी और इससे उनकी इनपुट लागत को कम करने में मदद मिलेगी। वर्तमान में यूरिया की एमआरपी 242 रुपये प्रति 45 किलोग्राम यूरिया की बोरी है (नीम कोटिंग शुल्क और लागू करों को छोड़कर), जबकि बैग की वास्तविक कीमत लगभग 2200 रुपये है। यह योजना पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा बजटीय सहायता के माध्यम से वित्तपोषित है। यूरिया सब्सिडी योजना के जारी रहने से जारी रहने से यूरिया का स्वदेशी उत्पादन भी अधिकतम होगा।

लगातार बदलती भू-राजनीतिक स्थिति और कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि के कारण पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक स्तर पर उर्वरक की कीमतें कई गुना बढ़ रही हैं, लेकिन भारत सरकार ने उर्वरक सब्सिडी बढ़ाकर अपने किसानों को उर्वरक की अधिक कीमतों से बचाया है। हमारे किसानों की सुरक्षा के अपने प्रयास में भारत सरकार ने उर्वरक सब्सिडी को 2014-15 में 73,067 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2022-23 में 2,54,799 करोड़ रुपये कर दिया है। ■

पिछले नौ वर्षों में देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई लगभग 59 प्रतिशत बढ़ी

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने 27 जून को कहा कि पिछले नौ वर्षों में देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई लगभग 59 प्रतिशत बढ़ी है। इस विस्तार के साथ ही भारत के पास अब अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है।

श्री गडकरी ने कहा कि 2013-14 में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 91,287 किलोमीटर थी, जो 2022-23 में बढ़कर 1,45,240 किलोमीटर हो गयी, जो इस अवधि में 59 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि है।

उन्होंने कहा कि पिछले नौ वर्षों में फोर-लेन राष्ट्रीय-राजमार्ग में वृद्धि लगभग दोगुनी हो गई है। 2013-14 में फोर-लेन राष्ट्रीय-राजमार्ग की यह लंबाई 18,371 किलोमीटर थी, जो पिछले नौ वर्षों में बढ़कर 44,654 किलोमीटर हो गयी है।

श्री गडकरी ने कहा कि फास्टैग को शुरु करने से टोल संग्रह में महत्वपूर्ण उछाल आया है। उन्होंने बताया कि टोल से राजस्व संग्रहण 2013-14 के 4,700 करोड़ रुपए से बढ़कर 2022-23 में 41,342 करोड़ रुपए हो गया है। श्री गडकरी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2030 तक टोल राजस्व संग्रहण को 1,30,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है।

उन्होंने कहा कि उत्तर पूर्व क्षेत्र में सड़क राजमार्ग नेटवर्क के विस्तार पर विशेष ज़ोर दिया जा रहा है और इस क्षेत्र में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक लागत की परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा के सुखद अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से सड़क किनारों पर 670 सुविधाएं विकसित की जा रही हैं।

हरित पहल के मुददे पर श्री गडकरी ने कहा कि एनएचएआई ने पिछले नौ वर्षों में 68,000 से अधिक पेड़ों का प्रत्यारोपण किया, जबकि 3.86 करोड़ नए पेड़ लगाए। जल पुनर्जीवन पहल के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि एनएचएआई ने देशभर में राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे 1500 से अधिक अमृत सरोवर विकसित किए हैं। ■

प्रधानमंत्री ने पांच नई 'वंदे भारत एक्सप्रेस' ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

भारतीय रेल 27 जून को एक ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बना, जब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन पर 'वंदे भारत एक्सप्रेस' ट्रेनों के पांच नए एवं उन्नत संस्करणों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

आरामदायक और उन्नत अनुभव वाली रेल यात्रा के एक नए युग की शुरुआत करते हुए रानी कमलापति-जबलपुर, रानी कमलापति-इंदौर, गोवा (मडगांव)-मुंबई, रांची-पटना और धारवाड़-बेंगलुरु के बीच पांच नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चल रही हैं।

रानी कमलापति-जबलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस

रानी कमलापति-जबलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से प्रस्थान करेगी और नरसिंहपुर, पिपरिया तथा नर्मदापुरम रेलवे स्टेशनों पर रुकते हुए उसी दिन जबलपुर स्टेशन पहुंचेगी।

वंदे भारत ट्रेन का परिचालन शुरू होने से मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी जबलपुर, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और आसपास के धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों की कनेक्टिविटी बढ़ने के साथ-साथ इस इलाके का सर्वांगीण विकास भी होगा।

रानी कमलापति-इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस

भोपाल-इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भोपाल रेलवे स्टेशन से प्रस्थान करेगी और उज्जैन रेलवे स्टेशन पर रुकते हुए उसी दिन इंदौर स्टेशन पहुंचेगी। रानी कमलापति से इंदौर के बीच वंदे भारत ट्रेन के चलने से यात्रा आसान और तेज होगी। साथ ही, यह इन इलाकों की संस्कृति, पर्यटन और तीर्थ स्थलों को जोड़ने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनेगी।

गोवा (मडगांव)-मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस

गोवा (मडगांव)-मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन से प्रस्थान करेगी और दादर, ठाणे, पनवेल, खेड़, रत्नागिरी, कंकावली तथा थिविम रेलवे स्टेशनों पर रुकते हुए उसी दिन मडगांव स्टेशन पहुंचेगी। यह अत्याधुनिक वंदे भारत एक्सप्रेस कोंकण क्षेत्र के लोगों को गति और आराम के साथ यात्रा करने का साधन उपलब्ध कराएगी। इससे इस इलाके में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

रांची-पटना वंदे भारत एक्सप्रेस

रांची-पटना नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पटना से प्रस्थान करेगी और गया, कोडरमा, हज़ारीबाग, बरकाकाना तथा मेसरा रेलवे स्टेशनों पर रुकते हुए उसी दिन रांची स्टेशन पहुंचेगी। प्रचुर मात्रा में खनिज संसाधनों से समृद्ध रांची खनिज आधारित उद्योगों के लिए एक आदर्श स्थान है। यह ट्रेन स्थानीय व्यापारियों और कारोबारियों के लिए पटना के साथ तेज कनेक्टिविटी स्थापित करने की दृष्टि से लाभदायक साबित होगी।

धारवाड़-बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस

धारवाड़-बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन केएसआर बेंगलुरु सिटी से प्रस्थान करेगी और यशवंतपुर, दावणगेरे तथा हुबली रेलवे स्टेशनों पर रुकते हुए उसी दिन धारवाड़ स्टेशन पहुंचेगी।

कर्नाटक में धारवाड़-बेंगलुरु वंदे भारत ट्रेन विद्या काशी धारवाड़, वाणिज्य नगरी, हुबली और बेंगलुरु को जोड़ेगी। यह वंदे भारत ट्रेन उत्तरी कर्नाटक को दक्षिणी कर्नाटक से जोड़ेगी।

उल्लेखनीय है कि प्रत्येक ट्रेन में 160 किमी प्रति घंटे की परिचालन गति के लिए पूरी तरह से सस्पेंडेड ट्रैक्शन मोटर से लैस बोगियां प्रदान की गई हैं। ■

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने संसद में राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक, 2023 को पेश करने को दी मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 28 जून को राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एनआरएफ) विधेयक, 2023 को संसद में पेश करने की स्वीकृति दे दी। स्वीकृत विधेयक राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एनआरएफ) की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करेगा। यह फाउंडेशन अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) का बीजारोपण करेगा तथा उसे विकसित एवं प्रोत्साहित करेगा और देशभर के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, अनुसंधान संस्थानों तथा अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) प्रयोगशालाओं में अनुसंधान एवं नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देगा।

यह विधेयक संसद में मंजूरी के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) की सिफारिशों के अनुरूप देश में वैज्ञानिक अनुसंधान को उच्चस्तरीय रणनीतिक दिशा प्रदान करने के लिए एनआरएफ नाम की एक शीर्ष निकाय की स्थापना करेगा। इस शीर्ष निकाय की कुल अनुमानित लागत पांच वर्षों की अवधि (2023-28) के दौरान 50,000 करोड़ रुपये होगी। ■

जून, 2023 के लिए सकल जीएसटी राजस्व संग्रह 12 प्रतिशत बढ़कर 1,61,497 करोड़ रुपये रहा

जीएसटी की शुरुआत के बाद से चौथी बार सकल जीएसटी संग्रह 1.6 लाख करोड़ रुपये; लगातार 16 महीनों तक 1.4 लाख करोड़ रुपये और शुरुआत के बाद से 7वीं बार 1.5 लाख रुपये के पार पहुंचा

केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा एक जुलाई को जारी विज्ञप्ति के अनुसार जून, 2023 में सकल जीएसटी राजस्व संग्रह 1,61,497 करोड़ रुपये रहा है, जिसमें से सीजीएसटी 31,013 करोड़ रुपये है, एसजीएसटी 38,292 करोड़ रुपये है, आईजीएसटी 80,292 करोड़ रुपये (माल के आयात पर एकत्र 39,035 करोड़ रुपये समेत) है और उपकर 11,900 करोड़ रुपये (माल के आयात पर एकत्र 1,028 करोड़ रुपये समेत) है।

केंद्र सरकार ने आईजीएसटी से सीजीएसटी के रूप में 36,224 करोड़ रुपये और एसजीएसटी के रूप में 30,269 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। नियमित भुगतान के बाद जून, 2023 के महीने में केंद्र और राज्यों का कुल राजस्व सीजीएसटी के लिए 67,237 करोड़ रुपये और एसजीएसटी के लिए 68,561 करोड़ रुपये है।

जून, 2023 महीने का राजस्व पिछले साल के इसी महीने के जीएसटी राजस्व से 12% अधिक है। इस महीने के दौरान घरेलू लेनदेन (सेवाओं के आयात सहित) से प्राप्त राजस्व पिछले वर्ष के इसी महीने के दौरान इन स्रोतों से प्राप्त राजस्व से 18% अधिक है।

यह चौथी बार है जब सकल जीएसटी संग्रह 1.60 लाख करोड़ रुपये की सीमा को पार कर गया है। वित्त वर्ष 2021-22, वित्त वर्ष 22-23 और वित्त वर्ष 23-24 की पहली तिमाही के लिए औसत मासिक सकल जीएसटी संग्रह क्रमशः 1.10 लाख करोड़ रुपये; 1.51 लाख करोड़ रुपये और 1.69 लाख करोड़ रुपये है। ■

पिछले 3 वर्षों में गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) से खरीद में 10 गुना बढ़ोतरी

31 मार्च, 2023 तक जीईएम ने वित्त वर्ष 2022-23 में 2 लाख करोड़ रुपये का विशाल सकल व्यापारिक मूल्य (जीएमवी) दर्ज किया

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल ने 26 जून को बताया कि पिछले तीन वर्षों में सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) से खरीद में '10 गुना' बढ़ोतरी हुई है।

उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकारी पोर्टल जीईएम से वस्तुओं और सेवाओं की कुल खरीद वित्त वर्ष 2022-23 में 3 लाख करोड़ रुपये को पार कर जाएगी, क्योंकि यह वर्ष 2022-23 में पहले ही 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो चुकी है।

उल्लेखनीय है कि जीईएम ने भारत में सरकारी खरीद के तरीके को रूपांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 2016 में स्थापित जीईएम का गठन देश के सार्वजनिक खरीद परिदृश्य में एक आमूलचूल परिवर्तन लाने के विजन के साथ किया गया था। इस प्लेटफ़ॉर्म ने खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और लागत-प्रभावशीलता को सक्षम बनाया, जिससे खरीदारों के लिए देश भर के विक्रेताओं से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद करना सरल हो गया है।

31 मार्च, 2023 तक जीईएम ने वित्त वर्ष 2022-23 में 2 लाख करोड़ रुपये का विशाल सकल व्यापारिक मूल्य (जीएमवी) दर्ज किया था। संचयी रूप से जीईएम ने अपने हितधारकों की भरपूर सहायता के साथ अपनी स्थापना के बाद से 4.29 लाख करोड़ रुपये के जीएमवी को पार कर लिया है। जीईएम पर लेन-देन की कुल संख्या भी 1.54 करोड़ रुपये से अधिक हो गई है। इस पोर्टल में 11,800 से अधिक उत्पाद श्रेणियों के साथ-साथ 280 से अधिक सेवा श्रेणियां शामिल हैं। विभिन्न अध्ययनों के आधार पर इस प्लेटफ़ॉर्म पर न्यूनतम बचत लगभग 10 प्रतिशत है, जो 40,000 करोड़ रुपये के सार्वजनिक धन की बचत में बदल जाती है।

दरअसल, केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा 9 अगस्त, 2016 को सरकारी ई-मार्केट (जीईएम) पोर्टल लॉन्च किया गया था। जीईएम के पास 63,000 से अधिक सरकारी खरीदार संगठन और 62 लाख से अधिक विक्रेता और सेवा प्रदाता हैं, जो उत्पादों और सेवाओं की एक व्यापक श्रृंखला प्रस्तुत करते हैं। ■

मोदी स्टोरी

मोदी का स्मार्ट चुनाव अभियान

—तेज बहादुर चौहान

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अपनी चुनावी रणनीतियों और लोगों से जुड़ने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाते हैं। उनके नवोन्वेषी सुझावों और लीक से हटकर विचारों ने पार्टी कार्यकर्ताओं को कड़ी मेहनत करना सिखाया है और उन्हें स्मार्ट बनाया है जिससे पिछले कई दशकों से भाजपा को पूरे देश में आगे बढ़ने में मदद मिली है।

2014 के बाद से विपक्षी दल श्री मोदी की चुनावी रणनीतियों के बारे में अनभिज्ञ रहे और यही एक कारण है कि देश ने श्री नरेन्द्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में चुना है।

हालांकि, श्री मोदी के स्मार्ट और नवोन्वेषी चुनाव अभियान भाजपा में उनके शुरुआती दिनों से ही पार्टी को चुनाव जीतने में मदद करते आये हैं।

यह बात वर्ष 1997-98 की है जब श्री नरेन्द्र मोदी मध्य प्रदेश भाजपा के प्रभारी थे और वह पार्टी की एक बैठक के लिए उज्जैन आये हुए थे।

मध्य प्रदेश के भाजपा नेता श्री तेज बहादुर चौहान उज्जैन में श्री नरेन्द्र मोदी के साथ अपनी बातचीत को याद करते हुए बताते है कि श्री मोदी ने उनसे उनकी जिम्मेदारियों और पार्टी द्वारा सौंपे गये कार्यों के बारे में चर्चा की। इस पर श्री चौहान ने उत्तर दिया कि वह पार्टी के झंडे और पर्चे बांटते हैं, हर घर में जाते हैं, शहर भर में लोगों से मिलते हैं और मतदाताओं को भाजपा को वोट देने के लिए प्रेरित करते हैं।

इसके बाद श्री मोदी ने उनसे उनके मूल स्थान को लेकर प्रश्न किया, साथ ही उनसे यह भी पूछा कि वह शहर भर में कितने झंडे बांटते हैं। श्री चौहान ने उत्तर दिया कि वे लगभग 15 हजार घरों वाले नागदा के निवासी हैं और शहर में 2500-3000 झंडे वितरित करते हैं।

उनका जवाब सुनकर श्री मोदी ने उनसे पूछा कि क्या आपके शहर में ऑटो रिक्शा चलते हैं। श्री मोदी के सवाल पर थोड़ा आश्चर्यचकित होते हुए श्री चौहान ने हां में जवाब दिया। तब श्री मोदी ने उन्हें सुझाव दिया कि आप 3000 पार्टी झंडे बांटने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपको वांछित परिणाम न मिले, जबकि यदि आप शहर में विभिन्न ऑटो रिक्शा पर 50 पार्टी के झंडे लगा सकते हैं, तो वे पूरे शहर में घूमेंगे और घरों पर लगाए गए 3000 पार्टी के झंडों की तुलना में लोगों के बीच पार्टी के झंडे को अधिक पहुंच प्रदान करेंगे।

श्री मोदी के सुझाव को पाकर श्री चौहान आश्चर्यचकित रह गये। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि यह एक सामान्य विचार प्रक्रिया थी, लेकिन इसका उन्हें कभी आभास नहीं हुआ। उनका कहना है कि श्री मोदी के सुझाव से उन्हें स्मार्ट तरीके से काम करने में मदद मिली और पार्टी के लिए बेहतर परिणाम मिले। ■

केंद्र सरकार ने वर्ष 2021-22 से 2025-26 के लिए स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फंड के लिए 1,28,122.40 करोड़ रुपये किए आवंटित

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 30 जून को स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फंड (एसडीआरएफ) के तहत 19 राज्य सरकारों को 6,194.40 करोड़ रुपये जारी करने की मंजूरी दी। इस राशि में वर्ष 2022-23 के लिए 4 राज्यों (छत्तीसगढ़, मेघालय, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश) को एसडीआरएफ के केन्द्रीय हिस्से के रूप में 1,209.60 करोड़ रुपये और 15 राज्यों (आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा) को वर्ष 2023-24 के लिए 4,984.80 करोड़ रुपये शामिल हैं। इस धनराशि का उपयोग राज्य मौजूदा मानसून सीज़न के दौरान राहत उपायों के लिए कर सकेंगे।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पहले ही वर्ष 2023-24 के दौरान 09 राज्यों को एसडीआरएफ के केन्द्रीय हिस्से के रूप में 3649.40 करोड़ रुपये जारी करने की मंजूरी दे दी है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार ने वर्ष 2021-22 से 2025-26 के लिए एसडीआरएफ के लिए 1,28,122.40 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। ■

अंधेरा छंटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा

अटल बिहारी वाजपेयी

मुंबई में आयोजित भाजपा राष्ट्रीय परिषद् में 28 दिसंबर, 1980 को श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा दिए गए अध्यक्षीय भाषण का अंतिम भाग—

असम आंदोलन

असम जल रहा है। गत एक वर्ष से वहां आग लगी हुई है। बड़ी संख्या में विदेशी नागरिकों की घुसपैठ के कारण वहां के लोग अपने ही घर में पराए होते जा रहे हैं। घुसपैठ का सिलसिला दशकों से चल रहा है। मुझे याद है, 1957 में जब मैं पहली बार लोकसभा का सदस्य बना तो मैंने इस घुसपैठ की ओर सरकार का ध्यान खींचा था। मैंने यह चेतावनी भी दी थी कि यदि घुसपैठ को रोकने की कोई प्रभावी उपाय योजना नहीं की गई तो परिस्थिति विस्फोटक रूप धारण कर लेगी। किंतु सरकार ने समस्या की गंभीरता को नहीं पहचाना। असम में विदेशियों की समस्या का आकार मामूली नहीं है, जैसा बताने की कोशिश होती रही है। 1978 में जनता शासन के दौरान अकेले मंगलदोई लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 47,600 विदेशियों के नाम मतदाता सूची में पाए गए। 1957 से 1970 के बीच यहां मतदाता सूची में 12 लाख मतदाताओं की बढ़ोतरी हुई, जबकि 1970 से 1979 के बीच यहां 28 लाख नए मतदाताओं के नाम दर्ज हुए।

असम में विदेशियों की समस्या

केंद्रीय सरकार के पिछले 12 महीनों के बर्ताव ने असम की समस्या को ज्यादा जटिल बना दिया है। सरकार ने कभी इसे असमी बनाम गैर-असमी का रंग देने की कोशिश की तो कभी असमी और बंगालियों में टकराव कराने की नीति अपनाई। कभी सवाल को हिंदू बनाम मुसलमान का रूप देने का प्रयास किया, लेकिन असम में विदेशियों की समस्या को असली रूप में देखने से हमेशा इनकार करती रही।

असम सीमा प्रदेश है। यह भौगोलिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। सामरिक दृष्टि से भारत का सिंहद्वार है। प्राकृतिक दृष्टि से मनोहारी

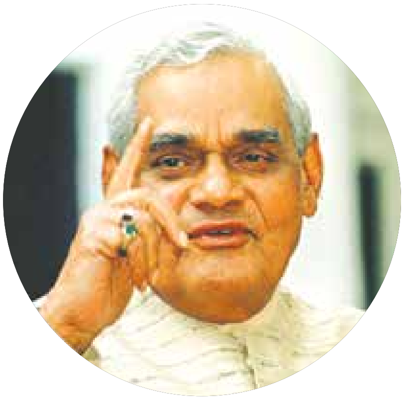

असम तेल, खनिज, वनसंपदा, जलस्रोतों और संस्कृति की दृष्टि से बड़ा संपन्न है। किंतु आज भी असम निर्धन है, निरादृत है, शोषित है, शापित है। असमी लोग अपने आर्थिक पिछड़ेपन के लिए केंद्र को दोषी मानते हैं। उन्हें यह भी शिकायत है कि उनकी भाषा तथा अन्य सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रति अवहेलना का रवैया अपनाया गया है।

केंद्रीय सरकार और आंदोलनकारी नेताओं के बीच बातों के जो अनेक दौर हुए हैं, उनके फलस्वरूप मतभेद घटे हैं और अब गतिरोध इस बात पर है कि 1961 से 1971 के बीच आए विदेशियों का क्या किया जाए। सरकार उन्हें असम से बाहर बसाने के लिए तैयार नहीं है, जबकि आंदोलन के नेता सारा बोझ असम पर डालने को उचित नहीं मानते।

दोनों पक्षों को इस मामले में अपने कड़े रुख में थोड़ा परिवर्तन करना चाहिए। बीच का रास्ता यह हो सकता है कि 1961 से 1971 के बीच आए लोगों को पहचानने तथा मतदाता सूची में से उनके नाम काटने पर दोनों पक्ष सहमत हो जाएं। ऐसे लोगों को असम में ही रहने दिया जाए या अन्य प्रदेशों में बसाया जाए, इस सवाल का निर्णय नई मतदाता सूचियों के आधार पर निर्वाचित नई सरकार पर छोड़ दिया जाए।

असम सरकार का गठन एक संवैधानिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए हुआ था, अब उसे बनाए रखने का कोई संवैधानिक, नैतिक या व्यावहारिक औचित्य नहीं है। उसे तुरंत बरखास्त कर देना चाहिए।

जनांदोलन को दबाना अनुचित

असम के जनांदोलन को गोली या गिरफ्तारी से नहीं दबाया जा सकता। जिस आंदोलन के साथ लगभग हर असमिया पुरुष, नारी तथा बच्चे की भावनाएं जुड़ी हैं, उसको केवल कानून तथा व्यवस्था के मामले के रूप में निबटाना आत्मघात होगा। दमन का रास्ता अमन का रास्ता नहीं हो सकता।

विदेशी घुसपैठ को बढ़ावा

असम की वर्तमान स्थिति के लिए वे राजनीतिक नेता दोषी हैं, जिन्होंने स्वार्थसिद्धि के लिए न केवल विदेशी घुसपैठ को अनदेखा किया, अपितु उसे बढ़ावा देने का अपराध भी किया। असम की आत्मा में पहले से ही बहुत से घाव लगे हैं। शेष भारत अपनी उदासीनता और केंद्रीय नेतृत्व अपनी अदूरदर्शिता से असम के पूर्ण विनाश का पाप न करे।

आर्थिक स्थिति : 1977 और 1980

देश के आर्थिक संकट को गहरा करने के लिए वर्तमान सरकार की नीतियां या नीतियों का पूर्ण अभाव, जिम्मेदार है। चीन में वर्षों का नामकरण करने की परंपरा है। वे किसी वर्ष को चंद्रमा का वर्ष और किसी को सिंह का वर्ष पुकारते हैं। यदि हम उनका अनुकरण करें तो श्रीमती गांधी के प्रथम वर्ष को 'घोंघे का वर्ष' कहना पड़ेगा। इसकी तुलना में जनता शासन

के दो वर्ष दौड़ते हुए घोड़े के वर्ष थे।

विकास की धीमी गति

गत वर्ष आर्थिक मोरचे पर पूरी जड़ता छाई रही। ऐसा लगा, मानो काल थम गया है। सबसे बुरा पहलू यह है कि सरकार को यह पता भी नहीं चला कि सबकुछ ठप है। वित्तमंत्री श्री वेंकटरमण बार-बार अपने आंकड़े बदलते रहे। उन्होंने जून में, जब अपना विनाशकारी बजट पेश किया था, यह कहा था कि औद्योगिक उत्पादन में 8 से 10 फीसदी तक की वृद्धि होगी। अब उन्हें स्वीकार करना पड़ा है कि वृद्धि 4 फीसदी से अधिक नहीं होगी। हमेशा की तरह इस बार भी वह गलत साबित होंगे। औद्योगिक विकास गत वर्ष से 2 प्रतिशत ही अधिक होगा।

बढ़ती मुद्रास्फीति

मूल्यवृद्धि को रोकने के आश्वासन पर चुनी गई सरकार के एक साल में दो ही चीजों में वृद्धि हुई है— पहला, मूल्य और दूसरा, शेयर बाजार शेष सबकुछ नीचे ही नीचे जा रहा है। जनता के शासनकाल में राष्ट्रीय आय में प्रतिवर्ष 6.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। इस वर्ष 3 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि नहीं होगी। जनता शासन में औद्योगिक उत्पादन 5.5 प्रतिशत की दर से बढ़ा था, इस वर्ष यह केवल 2 प्रतिशत बढ़ेगा। जनता शासन में मूल्य स्थिर थे, उनमें नाममात्र की भी वृद्धि नहीं हुई थी, इस वर्ष उनमें 20 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है और वे लगातार बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री का कहना है कि उन्होंने जनता पार्टी को एक अच्छी अर्थस्थिति सौंपी थी और जनता ने उसको तहस-नहस कर दिया। वह भूल जाती है कि 1976-77 में जनता शासन के एक वर्ष पूर्व सूखा पड़ा था। सूखा गत वर्ष भी पड़ा था। फिर भी जनता सरकार ने अच्छे परिणाम दिखाए तथा अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ; अब स्थिति उलट गई है।

घटता विदेशी मुद्रा भंडार

अच्छी आर्थिक स्थिति अच्छे विदेशी मुद्रा भंडार में दिखाई देती है। जनता शासन में विदेशी मुद्रा में 2350 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई थी और जब हमने सरकार छोड़ी तो देश के पास 5200 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा थी। तब से यह भंडार लगातार घट रहा है। प्रति वर्ष 600 करोड़ रुपए की कमी हो रही है। राष्ट्र की संपत्ति को उड़ाया जा रहा है।

केंद्रीय सरकार तथा योजना आयोग इस बात के लिए अपनी पीठ आप थपथपाते हुए नहीं थकते कि छठीं पंचवर्षीय योजना को बड़ी फुर्ती से अंतिम रूप दे दिया गया है। तथ्य यह है कि जनता शासन द्वारा तैयार पुरानी योजना को ही कांट-छांट तथा लीप-पोतकर नई योजना के रूप में पेश कर दिया गया है। इसके लिए सरकार को क्षमा किया जा सकता है। किंतु अब जो कुछ होनेवाला है और जिसके लिए शासन को कभी क्षमा नहीं किया जा सकता, वह है योजना को पूरी तरह रद करने की तैयारी। जिस तेजी से कीमतें बढ़ रही हैं, उससे योजना एक कागजी खिलौने से ज्यादा कुछ नहीं रही है।

हम इस बात पर संतोष करके न बैठें कि दुनिया के प्रथम 10 औद्योगिक देशों में भारत की गिनती होती है। हमारा स्थान पांचवां क्यों न हो? दुनिया तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। छोटा देश दक्षिण कोरिया जैसे भी हमें मीलों पीछे छोड़ चुका है। देश की अर्थव्यवस्था साइकिल पर चढ़े व्यक्ति की तरह होती है; पैडल चलाना बंद करते ही सवार गिर जाता है। सरकार पैडल चलाना कभी का बंद कर चुकी है। अब तो वह गिरनेवाली है।

देश तकदीर के तिराहे पर

किंतु सवाल केवल सरकार के गिरने या पूरी तरह विफल हो जाने का नहीं है। लोकतंत्र में सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी। सवाल तो यह है कि भारत राष्ट्र अपनी मूल्य-व्यवस्था के आधार पर वर्तमान काल की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर एक उज्ज्वल भविष्य का निर्माण करने में समर्थ होगा या नहीं।

मित्रो, स्थिति गंभीर है। देश एक बार फिर तकदीर के तिराहे पर खड़ा है। एक ओर अधिनायकवाद का खतरा है, तो दूसरी ओर अराजकता का संकट है। दोनों का सामना करने के लिए हमें लोगों को संगठित करना होगा। भारतीय जनता पार्टी टकराव की राजनीति को पसंद नहीं करती। किंतु हम टकराव से कतराएंगे भी नहीं।

लोकतंत्र की रक्षा

भारतीय लोकतंत्र के प्राण 65 करोड़ लोगों की समानता की उत्कट आकांक्षा और शोषण की स्थितियों से मुक्ति की तीव्र आतुरता में बसते हैं। जो लोकतंत्र से खिलवाड़ करना चाहते हैं, उन्हें इतिहास लोकचेतना की तूफानी धारा में बहाकर ले जाएगा।

आवश्यकता इस बात की है कि गणतंत्र की रक्षा और नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना के इस संघर्ष में हम किसानों, मजदूरों, ग्रामीण गरीबों, दस्तकारों, युवकों, छात्रों तथा महिलाओं को भागीदार बनाएं तथा उनमें यह विश्वास पैदा करें कि अपनी स्थिति को सुधारने का उनका यत्न यथास्थिति को एकजुट होकर बदलने से ही पूरा होगा।

लोकतंत्र और सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष का आह्वान भारतीय जनता पार्टी राजनीति में, राजनीतिक दलों में तथा राजनेताओं में जनता के खोए हुए विश्वास को पुनः स्थापित करने के लिए जमीन से जुड़ी राजनीति करेगी। शिखर की राजनीति के दिन लद गए। जोड़-तोड़ की राजनीति का कोई भविष्य अब नहीं रहा। पद, पैसा और प्रतिष्ठा के पीछे पागल होनेवालों के लिए हमारे यहां कोई जगह नहीं है। जिनमें आत्मसम्मान का अभाव हो, वे दरबार में जाकर मुजरे झाड़ें, हम तो एक हाथ में भारत का संविधान और दूसरे में समता का निशान लेकर मैदान में जूझेंगे। हम छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन और संघर्ष से प्रेरणा लेंगे। सामाजिक समता का बिगुल बजाने वाले महात्मा फूले हमारे पथ-प्रदर्शक होंगे।

कमल खिलेगा

देश के पश्चिमी घाट को मंडित करनेवाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं यह भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं कि 'अंधेरा छंटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा।' **वंदेमातरम्** ■ **समाप्त**

राज्यसभा सांसद हरद्वार दुबे नहीं रहे

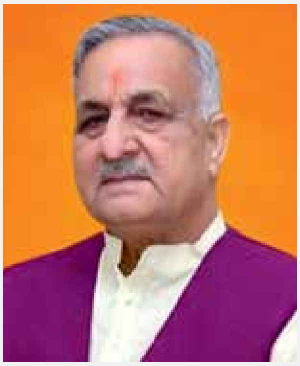

भाजपा नेता और उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद श्री हरद्वार दुबे का 26 जून को निधन हो गया। वह 74 वर्ष के थे।

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री दुबे के निधन पर शोक व्यक्त किया।

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने निधन पर दुख व्यक्त करते हुए कहा, "राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री श्री हरद्वार दुबे जी के निधन का समाचार दुःखद है। वे जनसेवा के लिए समर्पित रहे। शोक संतप्त परिवारजनों व समर्थकों के प्रति मेरी गहन संवेदनाएं।"

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा, "भाजपा के कर्मठ सांसद हरद्वार दुबे जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। वे जमीन से जुड़े एक ऐसे नेता थे, जो उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा में अपने अहम योगदान के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। शोक की इस घड़ी में ईश्वर उनके परिजनों और प्रशंसकों को संबल प्रदान करे।"

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने शोक व्यक्त करते हुए एक ट्वीट में कहा, "वरिष्ठ भाजपा नेता व उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद हरद्वार दुबे जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है। आपका संपूर्ण जीवन जनसेवा व संगठन को समर्पित रहा। आपका जाना संगठन के लिए अपूरणीय क्षति है। शोकाकुल परिजनों के प्रति गहन संवेदना प्रकट करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना है कि परिजनों को संबल प्रदान करें व दिवंगत आत्मा को श्री चरणों में स्थान दें।"

एक ट्वीट में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) श्री बी.एल. संतोष ने शोक व्यक्त करते हुए कहा, "यूपी से राज्यसभा सांसद श्री हरिद्वार दुबे, 74 वर्ष, ने संक्षिप्त बीमारी के बाद आज अंतिम सांस ली। वह अपनी सत्यनिष्ठा और समाज के प्रति करुणा के लिए जाने जाते थे। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति दे और प्रियजनों को यह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें।"

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुःख व्यक्त करते हुए कहा कि श्री दुबे का निधन बहुत दुःखद है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, ''माननीय राज्यसभा सांसद, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री हरिद्वार दुबे जी का निधन अत्यंत दुःखद है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। प्रभु श्री राम दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान तथा शोकाकुल परिजनों को यह अथाह दुःख सहने की शक्ति दें।''

श्री हरद्वार दुबे का जन्म 1 जुलाई, 1949 को हुसैनाबाद, बलिया, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने आगरा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् (एबीवीपी) के संगठन मंत्री के रूप में काम किया। उनका विवाह प्रोफेसर कमला पांडे से हुआ था।

श्री हरद्वार दुबे ने 1989 में आगरा छावनी से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और विजयी रहे। उन्होंने कांग्रेस के कद्दावर नेता डॉ. कृष्णवीर सिंह कौशल को हराया था। 1991 में वह दोबारा विधायक बने और कल्याण सिंह की सरकार में वित्त राज्य मंत्री बनाए गए। 2013 में उन्हें उत्तर प्रदेश में भाजपा के उपाध्यक्ष और प्रवक्ता का दायित्व दिया गया। उन्होंने 26 नवंबर, 2020 को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। ■

हल्के लड़ाकू विमान तेजस ने भारतीय वायु सेना में सेवा के सात वर्ष किए पूरे

एक जुलाई, 2023 को स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान (एलसीए) ने भारतीय वायुसेना में अपनी सेवा के सात वर्ष पूरे कर लिए। 2003 में तेजस नाम से जाना जाने वाला यह विमान, एक बहु आयामी वायुयान है, जो अपनी श्रेणी में श्रेष्ठ में से एक है। इसे वायु रक्षा, समुद्री सर्वेक्षण और प्रहार भूमिका निभाने के लिए तैयार किया गया है। स्वाभाविक रूप से अस्थिर (inherently unstable) तेजस निश्चित संचालन और बेहतर गति प्रदान करता है। इस क्षमता को इसके मल्टीमोड एयरबोर्न रडार, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, सेल्फ प्रोटेक्शन सूट व लेज़र डेजिग्नेशन पॉड से लैस कर और बेहतर किया गया है।

भारतीय वायु सेना ने तेजस पर जो भरोसा जताया है, वह उसके 83 'एलसीए एमके-1ए' के खरीद ऑर्डर से पैदा हुआ है, जिसमें अद्यतन अवियोनिक्स के अलावा एक एक्टिव इलेक्ट्रानिकली स्टिरॉयड रडार, अद्यतन इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट और एक बियोंड विजुअल रेंज मिसाइल क्षमता होगी। तेजस का नया संस्करण बढ़ी हुई दूरी से अधिक हथियारों को दागने में सक्षम होगा। इनमें से कई हथियार स्वदेशी होंगे। ■

जनता को कांग्रेस का परिवारवाद नहीं, भाजपा का विकासवाद चाहिए: नरेन्द्र मोदी

बीकानेर, राजस्थान

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 8 जुलाई, 2023 को बीकानेर, राजस्थान में आयोजित एक जनसभा में कहा कि जनता तक विकास पूरी तरह से तब पहुंच पाता है, जब देश-प्रदेश की सरकारें साथ मिलकर ईमानदारी से काम करें। लेकिन राजस्थान को दिल्ली से योजनाओं का पैसा भेजते हैं तो यहां कांग्रेस का पंजा झपट्टा मार देता है कांग्रेस सरकार ने चार साल में राजस्थान का बहुत नुकसान किया है। और ये बात कांग्रेस के नेता भी अच्छी तरह से जानते हैं। तभी तो कुछ मंत्री-विधायक अभी से सरकारी बंगले खाली करने लगे हैं। अपनी हार पर इतना भरोसा सिर्फ कांग्रेस के नेता ही कर सकते हैं। राजस्थान में कांग्रेस की पहचान भ्रष्टाचार, अपराध और तुष्टीकरण करने की बन गई है। इसलिए राजस्थान की जनता को कांग्रेस का परिवारवाद नहीं, भाजपा का विकासवाद चाहिए। उन्होंने कहा कि घर-घर पीने का साफ पानी पहुंचाने की भाजपा सरकार की योजना से भी कांग्रेस को परेशानी है। आज देश के 130 से ज्यादा जिले ऐसे हैं, जहां शत-प्रतिशत घरों में नल से जल पहुंच रहा है। इनमें से राजस्थान का एक भी जिला नहीं है।

विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आठ जुलाई को राजस्थान के बीकानेर में 24,300 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। जिन परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया, उनमें शामिल हैं— अमृतसर-जामनगर आर्थिक गलियारे का छह-लेन वाला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे खंड, जिसे लगभग 11,125 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित किया गया है; लगभग 10,950 करोड़ रुपये की लागत से हरित ऊर्जा गलियारे के अंतर-राज्य ट्रांसमिशन लाइन का चरण-I; लगभग 1,340 करोड़ रुपये की लागत से बीकानेर पावर ग्रिड द्वारा विकसित भिवाड़ी ट्रांसमिशन लाइन और बीकानेर में 30 बिस्तरों वाला कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) अस्पताल। ■

'आज तेलंगाना में ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है, जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप नहीं हैं'

वारंगल, तेलंगाना

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 8 जुलाई, 2023 को वारंगल में आयोजित एक जनसभा में कहा कि भारत की आत्मनिर्भरता में तेलंगाना की बहुत बड़ी भूमिका है। पिछले 9 वर्षों में केंद्र सरकार ने तेलंगाना के विकास के लिए पूरी शक्ति से काम किया है। 2014 में तेलंगाना के लिए जो रेल बजट था, आज उसका 17 गुना अधिक रेल बजट उसके पास है। हमारा लक्ष्य है कि तेलंगाना विकसित बने और देश को भी विकसित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए।

श्री मोदी ने भ्रष्टाचार पर वार करते हुए कहा कि हम पहले दो देशों या दो राज्यों की सरकारों के बीच विकास से जुड़े समझौतों के बारे में सुनते थे, लेकिन ये पहली बार हुआ है, जब दो राजनीतिक दलों और दो राज्य सरकारों पर भ्रष्टाचार की डील के आरोप लगे हैं। आज तेलंगाना में ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है, जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप नहीं हैं। केसीआर सरकार यानी सबसे भ्रष्ट सरकार के तार अब तो दिल्ली तक फैल गए हैं।

श्री मोदी ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए भाजपा सरकार गांवों में ज्यादा से ज्यादा खर्च कर रही है, लेकिन केसीआर सरकार यहां ग्राम पंचायतों के सामने लगातार मुश्किलें खड़ी कर रही है। इसलिए इनमें सरकार के खिलाफ नाराजगी है।

विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आठ जुलाई को तेलंगाना के वारंगल में लगभग 6,100 करोड़ रुपये की लागत वाली कई महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। विकास कार्यों में 5,550 करोड़ रुपये से अधिक की 176 किलोमीटर लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं और काजीपेट में 500 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से विकसित की जाने वाली एक रेलवे विनिर्माण इकाई भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने भद्रकाली मंदिर में दर्शन और पूजा-अर्चना भी की। ■

12,100 करोड़ रुपये से ज्यादा लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास

वाराणसी, उत्तर प्रदेश

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सात जुलाई को वाराणसी, उत्तर प्रदेश में 12,100 करोड़ रुपये से ज्यादा की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन-सोन नगर रेलवे लाइन, विद्युतीकरण या दोहरीकरण पूरा होने के बाद तीन रेलवे लाइनों, एनएच-56 के वाराणसी-जौनपुर खंड का चार-लेन चौड़ीकरण और वाराणसी में कई परियोजना को समर्पित किया जाना शामिल है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी।

उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि श्रावण के पवित्र महीने की शुरुआत, भगवान विश्वनाथ और मां गंगा के आशीर्वाद और वाराणसी के लोगों की उपस्थिति से जीवन धन्य हो जाता है। श्री मोदी ने नागरिकों के आतिथ्य सत्कार पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जो भी वाराणसी आ रहा है, हमेशा सुखद अहसास के साथ वापस लौटेगा। उन्होंने जी-20 के प्रतिनिधियों का स्वागत करने और पूजा स्थलों के परिसरों को स्वच्छ और भव्य बनाए रखने के लिए काशी के लोगों की प्रशंसा की।

प्रधानमंत्री ने दो वंदे भारत ट्रेनों को झंडी दिखाकर किया रवाना

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सात जुलाई को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर रेलवे स्टेशन से दो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को झंडी दिखाकर रवाना किया। दो वंदे भारत ट्रेन हैं— गोरखपुर-लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस और जोधपुर-अहमदाबाद (साबरमती) वंदे भारत एक्सप्रेस। प्रधानमंत्री ने लगभग 498 करोड़ रुपए की लागत से गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का शिलान्यास भी किया और गोरखपुर रेलवे स्टेशन के प्रस्तावित मॉडल का निरीक्षण किया। ■

'छत्तीसगढ़ सरकार भ्रष्टाचार और कुशासन का मॉडल बन गई है'

रायपुर, छत्तीसगढ़

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 7 जुलाई, 2023 को रायपुर, छत्तीसगढ़ में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा, "छत्तीसगढ़ के निर्माण में भाजपा का महत्वपूर्ण योगदान रहा। हम छत्तीसगढ़ के लोगों के बारे में गहरी समझ रखते हैं और उनकी आवश्यकताओं से भली-भांति परिचित हैं। परिणामस्वरूप केंद्र की भाजपा सरकार छत्तीसगढ़ की तीव्र प्रगति के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।''

अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफल रहने के लिए कांग्रेस पार्टी पर हमला करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, "कांग्रेस द्वारा छत्तीसगढ़ से किए गए छत्तीस वादों में से एक प्रदेश में शराब पर प्रतिबंध लगाने का संकल्प था। हालांकि, कांग्रेस शराबबंदी लागू करने के बजाय छत्तीसगढ़ में हजारों करोड़ रुपये के शराब घोटाले में शामिल रही है। इससे पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ के साथ-साथ प्रदेश की माताओं-बहनों के साथ भी विश्वासघात किया है।

उन्होंने कहा, "आज छत्तीसगढ़ सरकार कांग्रेस के भ्रष्टाचार और कुशासन का मॉडल बन गई है। इसलिए आज पूरे छत्तीसगढ़ से एक ही आवाज उठ रही है- 'बदलबी, बदलबो,...ए डरी कांग्रेस के सरकारले बदलबो।"

रायपुर में लगभग 7,500 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सात जुलाई को छत्तीसगढ़ के रायपुर में लगभग 7,500 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया और इन्हें राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने करीब 6,400 करोड़ रुपये की 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत के तहत लाभार्थियों को 75 लाख कार्डों के वितरण का शुभारंभ किया। ■

आतंकवाद क्षेत्रीय, वैश्विक शांति के लिए प्रमुख खतरा; निर्णायक कार्रवाई जरूरी: नरेन्द्र मोदी

आतंकवाद चाहे किसी भी रूप में हो, किसी भी अभिव्यक्ति में हो, हमें इसके विरुद्ध मिलकर लड़ाई लड़नी होगी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आंतकवाद को क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के लिए प्रमुख खतरा करार देते हुए चार जुलाई को कहा कि कुछ देश सीमा पार आतंकवाद को अपनी नीतियों के औजार के रूप में इस्तेमाल करते हैं और आतंकवादियों को पनाह देते हैं तथा शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) को ऐसे देशों की आलोचना करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने डिजिटल माध्यम से 23वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह बात कही। बैठक में चीन के राष्ट्रपति श्री शी चिनफिंग, रूसी राष्ट्रपति श्री व्लादिमीर पुतिन आदि ने हिस्सा लिया।

श्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद चाहे किसी भी रूप में हो, किसी भी अभिव्यक्ति में हो, हमें इसके विरुद्ध मिलकर लड़ाई लड़नी होगी।

उन्होंने कहा कि कुछ देश सीमा पार आतंकवाद को अपनी नीतियों के औजार के रूप में इस्तेमाल करते हैं, आतंकवादियों को पनाह देते हैं और एससीओ को ऐसे देशों की आलोचना करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए।

अफगानिस्तान का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अफ़ग़ानिस्तान को लेकर भारत की चिंताएं और अपेक्षाएं एससीओ के अधिकांश देशों के समान हैं। हमें अफगानिस्तान के लोगों के कल्याण के लिए मिलकर प्रयास करने होंगे।

श्री मोदी ने कहा कि 2021 के घटनाक्रम के बाद भी हम मानवीय सहायता भेजते रहे हैं। यह आवश्यक है कि अफगानिस्तान की भूमि पड़ोसी देशों में अस्थिरता फैलाने या चरमपंथी विचारधाराओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयोग न की जाए।

खाद्यान्न, ईंधन और उर्वरक संकट सभी देशों के लिए एक बड़ी चुनौती

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि वर्तमान समय में वैश्विक स्थिति एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर है। विवादों, तनावों और महामारी से घिरे विश्व में खाद्यान्न, ईंधन और उर्वरक संकट सभी देशों के लिए एक बड़ी चुनौती है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें मिलकर यह विचार करना चाहिए कि क्या हम एक संगठन के रूप में हमारे लोगों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने में समर्थ है? क्या हम आधुनिक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है? क्या एससीओ एक ऐसा संगठन बन रहा है, जो भविष्य के लिए पूरी तरह से तैयार है?

उन्होंने कहा कि पिछले दो दशकों में शंघाई सहयोग संगठन पूरे यूरेशिया क्षेत्र में, शान्ति, समृद्धि और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफार्म के रूप में उभरा है। श्री मोदी ने कहा कि इस क्षेत्र के साथ भारत के हजारों वर्ष पुराने सांस्कृतिक और लोगों के बीच संबंध हमारी साझा विरासत का जीवंत प्रमाण हैं।

उन्होंने कहा कि एससीओ के अध्यक्ष के रूप में भारत ने हमारे बहुआयामी सहयोग को नयी ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए निरंतर प्रयास किये हैं। श्री मोदी ने कहा कि इन सभी प्रयासों को हमने दो मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित किया है। इसमें पहला 'वसुधैव कुटुम्बकम' यानी पूरी धरती हमारा परिवार है और दूसरा सुरक्षा, अर्थव्यवस्था एवं व्यापार, संपर्क, एकता, संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान और पर्यावरण है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने एससीओ में सहयोग के पांच नए स्तंभ बनाए हैं, जिसमें स्टार्टअप एवं नवाचार, पारंपरिक औषधि, डिजिटल समावेशिता और युवा सशक्तीकरण, साझी बौद्ध धरोहर शामिल हैं।

उल्लेखनीय है कि शंघाई सहयोग संगठन में भारत, रूस, चीन, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं तथा भारत ने एससीओ की अध्यक्षता पिछले वर्ष 16 सितंबर को समरकंद शिखर सम्मेलन के दौरान संभाली थी। ■

दिल्ली विश्वविद्यालय सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं है, बल्कि एक आंदोलन है: नरेन्द्र मोदी

जहां 2014 में क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में केवल 12 भारतीय विश्वविद्यालय थे, वहीं आज यह संख्या 45 तक पहुंच गई है

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 30 जून को दिल्ली विश्वविद्यालय के खेल परिसर के बहुउद्देशीय हॉल में दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैम्पस में बनने वाले फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर सेंटर और अकादमिक ब्लॉक के भवन की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने स्मारक शताब्दी खंड— शताब्दी समारोह का संकलन, लोगो बुक-दिल्ली विश्वविद्यालय और इसके कॉलेजो का लोगो; औरा - दिल्ली विश्विविद्यालय के सौ वर्ष का लोकार्पण किया।

श्री मोदी ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय का शताब्दी समारोह ऐसे समय में हो रहा है जब भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के बाद आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी देश के विश्वविद्यालय और शैक्षणिक संस्थान उसकी उपलब्धियों का प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि डीयू की 100 साल की यात्रा में कई ऐतिहासिक अवसर रहे हैं, जिन्होंने अनेक विद्यार्थियों, शिक्षकों और अन्य लोगों के जीवन को जोड़ा है। उन्होंने टिप्पणी की कि दिल्ली विश्वविद्यालय सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं है, बल्कि एक आंदोलन है।

उन्होंने कहा कि जब किसी व्यक्ति या संस्था का संकल्प देश के प्रति होता है, तो उसकी उपलब्धियों को राष्ट्र की उपलब्धियों के बराबर माना जाता है। श्री मोदी ने कहा कि जब दिल्ली विश्वविद्यालय प्रारंभ हुआ था, तब इसके अंतर्गत केवल 3 कॉलेज थे, लेकिन आज इसके अंतर्गत 90 से अधिक कॉलेज हैं। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि भारत जिसे कभी एक नाजुक अर्थव्यवस्था माना जाता था, अब विश्व की शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया है।

नई सदी का तीसरा दशक भारत की विकास यात्रा को गति देगा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि पिछली सदी के तीसरे दशक ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष को नई गति दी, अब नई सदी का तीसरा दशक भारत की विकास यात्रा को गति देगा। प्रधानमंत्री ने बड़ी संख्या में स्थापित होने वाले विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, आईआईटी, आईआईएम और एम्स का संकेत दिया। उन्होंने कहा कि ये सभी संस्थान नए भारत के बिल्डिंग ब्लॉक बन रहे हैं।

श्री मोदी ने बताया कि जहां 2014 में क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में केवल 12 भारतीय विश्वविद्यालय थे, वहीं आज यह संख्या 45 तक पहुंच गई है।

श्री मोदी ने आज के युवाओं की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने शिक्षा की अवधारणा को प्लेसमेंट और डिग्री तक सीमित न रखकर इसे आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि वे अपनी स्वयं की राह बनाना चाहते हैं और एक लाख से अधिक स्टार्टअप, 2014-15 की तुलना में 40 प्रतिशत अधिक पेटेंट फाइलिंग और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में वृद्धि को इस सोच के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया है।

उल्लेखनीय है कि दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना 1 मई, 1922 को हुई थी। अब विश्वविद्यालय में 86 विभाग, 90 कॉलेज और 6 लाख से अधिक विद्यार्थी हैं।

प्रधानमंत्री ने दिल्ली विश्वविद्यालय पहुंचने के लिए मेट्रो की सवारी की

प्रधानमंत्री ने दिल्ली विश्वविद्यालय पहुंचने के लिए मेट्रो की सवारी की। उन्होंने यात्रा के दौरान छात्रों के साथ बातचीत भी की। प्रधानमंत्री ने यहां पहुंचने पर प्रदर्शनी '100 वर्षों की यात्रा' का अवलोकन किया। उन्होंने संगीत और ललित कला संकाय द्वारा प्रस्तुत सरस्वती वंदना और विश्वविद्यालय कुलगीत को भी सुना। ■

एनईपी 2020 भारत के बच्चों के भविष्य को बदल रहा है

विष्णु दत्त शर्मा

आज भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। वैश्विक महाशक्ति बनने की हमारी आकांक्षाओं को प्राप्त करने की दिशा में कदम उठाने का यह सबसे योग्य क्षण है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने पहले से ही अत्यधिक कुशल कार्यबल द्वारा संचालित एक मजबूत और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था हासिल करने की दिशा में काम शुरू कर दिया है।

आने वाले दशक में भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने का अनुमान है और यह सिर्फ शुरुआत है! भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2023 का अनुमान है कि भारत के स्कूलों में 26 करोड़ से अधिक छात्र हैं। आने वाले 25 वर्षों में ये छात्र सबसे बड़े वैश्विक कार्यबल का हिस्सा बनेंगे और India@100 की आकांक्षाओं को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएंगे।

समकालीन दुनिया की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार की गई नई शिक्षा नीति का निर्माण भारतीय जनता पार्टी के 2014 के राष्ट्रीय चुनाव घोषणापत्र में भी एजेंडे में था। एक ऐसी शिक्षा नीति तैयार करने के लिए, जो हमारे छात्रों को 21वीं सदी के लिए सही कौशल सेट के साथ सशक्त बनाएगी, लाखों हितधारकों के साथ लगभग छह वर्षों तक परामर्श किया गया। NEP 2020 को 29 जुलाई, 2020 को भारत की तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति और 1986 के बाद पहली बार मंजूरी दी गई थी।

एक नीति के रूप में, जो बात NEP 2020 को अपने पूर्ववर्तियों से अलग करती है, वह स्कूली शिक्षा के दो पहलुओं पर जोर है— शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और कक्षाओं में बच्चों के सीखने के तरीके में बदलाव। यह शिक्षकों की क्षमता निर्माण के बारे में भी व्यापक रूप से बात करती है, जो हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं, आखिरकार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों के बिना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती है। अतीत की कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकारों द्वारा जारी की गई शिक्षा नीतियां मुख्य रूप से सभी बच्चों के लिए स्कूलों की पहुंच और उन्हें स्कूल तक पहुंचाने पर केंद्रित थीं, लेकिन NEP 2020 के हस्तक्षेप बच्चे की शैक्षणिक यात्रा के सभी चरणों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने पर केंद्रित हैं। बुनियादी स्तर से लेकर उनके स्कूल के अंत तक, उन्हें रोजगार योग्य, पूर्ण नागरिक बनाना।

हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के शब्दों में, यह नीति की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि "बच्चों को कक्षा-3 तक 'पढ़ना-सीखना' चाहिए ताकि वे बाद में 'सीखने के लिए पढ़ सकें'।'' शिक्षक पर्व 2022 के दौरान भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने उच्चतम गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार की राजनीतिक इच्छाशक्ति और प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा, "वर्तमान में, प्राथमिक विद्यालय स्तर के कई छात्रों को मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता (FLN) कौशल प्राप्त करने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसीलिए 2025 तक इन्हें हासिल करने को सबसे बड़ी प्राथमिकता दी गई है।"

सभी बच्चों को FLN कौशल प्रदान करने के लिए 2021 में NIPUN भारत मिशन का शुभारंभ कक्षा में शिक्षण और सीखने के तरीके में एक 'आदर्श बदलाव' है, जिसमें परीक्षा पास करने के लिए रटने के बजाय बच्चों के आवश्यक कौशल विकसित करने पर एक नया ध्यान केंद्रित किया गया है।

विज्ञान, गणित आदि जैसे विषयों को पढ़ाने के लिए घरेलू भाषा/मातृभाषा की शुरुआत हमारे बच्चों के जीवन में एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन है। इससे उन्हें अपनी संस्कृति, दृष्टिकोण और इतिहास से जुड़ने में मदद मिलेगी, जिससे उन्हें अपने स्थानीय समुदायों के प्रति जुड़ाव और गर्व की भावना मिलेगी। संस्कृति और मूल्य गतिशील NEP 2020 के लिए मौलिक हैं, हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसे एक गतिशील, समकालीन नीति के रूप में विकसित किया गया है।

जैसे-जैसे हमारे बच्चे अपनी शैक्षणिक यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं, NEP 2020 भारत को उद्यमिता और नवाचार का 'हब' बनाने के लिए उनका लाभ उठाने की दिशा में संरेखित है। आज, भारत के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टार्ट-अप इकोसिस्टम है, और NEP 2020 के भीतर 'स्टार्ट-अप इंडिया', 'कौशल विकास योजना' और 'अटल इनोवेशन मिशन' जैसे नीतिगत पहलों के माध्यम से मोदी सरकार ने दुनिया के सबसे बड़े टैलेंट पूल के अपस्किलिंग का समर्थन किया है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एक महत्वपूर्ण बात कही है, हमारी भावी पीढ़ियों को दुनिया की अग्रणी 'जॉब-क्रिएटर' बनना चाहिए। 2021-22 में, भारतीय स्टार्ट-अप ने रिकॉर्ड 35 बिलियन डॉलर जुटाए, और 2022-23 में 24 बिलियन डॉलर की फंडिंग की। यह भारतीय युवाओं और सृजन एवं नवप्रवर्तन के प्रति उनकी भूख का प्रमाण है और आने वाली चीजों का संकेत है। वे भारत के युवाओं में मौजूद आत्मनिर्भरता की भावना और दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए उत्साह, प्रेरणा और भूख का एक चमकदार उदाहरण हैं।

NEP 2020 मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई एक अभूतपूर्व और दूरदर्शी नीति है, जो दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी को उनकी क्षमताओं का दोहन करने के लिए सशक्त बना रही है। इसी सन्दर्भ में, भारत के शिक्षा क्षेत्र के लिए दृष्टिकोण और महत्वाकांक्षा को राजनीतिक इच्छाशक्ति और कार्यान्वयन द्वारा बढ़ाया गया है। उदाहरण के लिए, केंद्रीय बजट 2023-24 में शिक्षा क्षेत्र के लिए 1.12 लाख करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया गया था, जिसका लक्ष्य India@100 को प्रौद्योगिकी-संचालित और ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था बनाना है। आज यह अभूतपूर्व नीति तीन साल का मील का पत्थर पूरा कर रही है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह अभी से ही भारत की विकास कहानी में गेम-चेंजर साबित हो रही है। ■

(लेखक भाजपा, मध्यप्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद हैं)

चीनी सीजन 2023-24 के लिए 315 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य को मिली मंजूरी

चीनी सीजन 2023-24 के लिए गन्ने के उत्पादन की लागत 157 रुपये प्रति क्विंटल है। 315 रुपये प्रति क्विंटल की रिकवरी दर पर यह गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य; उत्पादन लागत से 100.06 प्रतिशत से अधिक है

गन्ना किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों पर कैबिनेट कमिटी (सीसीईए) ने 10.25 प्रतिशत की मूलभूत रिकवरी दर के लिए 315 रुपये प्रति क्विंटल पर चीनी सीजन 2023-24 (अक्टूबर-सितंबर) के लिए गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) को मंजूरी दे दी।

इसके अतिरिक्त, गन्ना किसानों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने यह भी निर्णय किया है कि उन चीनी मिलों के मामलों में कोई कटौती नहीं होगी, जहां रिकवरी 9.5 प्रतिशत से कम है। ऐसे किसानों को चालू चीनी सीजन 2022-23 में 282.125 रुपये प्रति क्विंटल के स्थान पर आगामी चीनी सीजन 2023-24 में गन्ने के लिए 291.975 रुपये प्रति क्विंटल प्राप्त होंगे।

चीनी सीजन 2023-24 के लिए गन्ने के उत्पादन की लागत 157 रुपये प्रति क्विंटल है। 315 रुपये प्रति क्विंटल की रिकवरी दर पर यह एफआरपी उत्पादन लागत से 100.06 प्रतिशत से अधिक है। चीनी सीजन 2023-24 के लिए एफआरपी वर्तमान चीनी सीजन 2022-23 की तुलना में 3.28 प्रतिशत अधिक है।

मंजूरी की गई एफआरपी चीनी मिलों द्वारा चीनी सीजन 2023-24 (1 अक्टूबर, 2023 से आरंभ) में किसानों से गन्ने की खरीद के लिए लागू होगी। चीनी सेक्टर एक महत्वपूर्ण कृषि-आधारित सेक्टर है जो लगभग 5 करोड़ गन्ना किसानों की आजीविका को और उनके आश्रितों तथा चीनी मिलों में प्रत्यक्ष रूप से कार्यरत लगभग 5 लाख श्रमिकों के अतिरिक्त कृषि श्रमिकों एवं परिवहन सहित

विभिन्न सहायक कार्यकलापों से जुटे लोगों को प्रभावित करता है।

उल्लेखनीय है कि वर्तमान चीनी सीजन 2022-23 में चीनी मिलों द्वारा 1,11,366 करोड़ रुपये के मूल्य लगभग 3,353 लाख टन गन्ने की खरीद की गई, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की फसल की खरीद के बाद दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है।

गौरतलब है कि भारत अब वैश्विक चीनी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, क्योंकि यह विश्व में चीनी का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। चीनी सीजन 2021-22 में भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश भी बन गया है। ऐसी उम्मीद की जाती है कि भारत वित्त वर्ष 2025-26 तक विश्व में तीसरा सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक देश बन जाएगा। ■

महाराष्ट्र में एनडीए सरकार में अजित पवार ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली

एनसीपी के 8 अन्य नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के वरिष्ठ नेता श्री अजीत पवार एवं आठ अन्य नेता एनडीए सरकार में शामिल हुए और मंत्री पद की शपथ ली। महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री रमेश बैस ने 2 जुलाई, 2023 को मुंबई के राजभवन में आयोजित एक समारोह में इन्हें शपथ दिलाई।

श्री अजीत पवार, श्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में शामिल हुए और उन्होंने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। आठ अन्य राकांपा नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। मंत्री पद की शपथ लेने वालों में श्री छगन भुजबल, श्री दिलीप वलसे पाटिल, श्री हसन मुश्रीफ, श्री धनंजय मुंडे, सुश्री अदिति तटकरे, श्री

धर्मराव अत्राम, श्री अनिल पाटिल और श्री संजय बनसोडे शामिल हैं। ■

डेयरी क्षेत्र में महिलाओं का योगदान लगभग 60 प्रतिशत है: नरेन्द्र मोदी

पिछले 9 वर्षों में सिर्फ उर्वरक सब्सिडी पर 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए गए हैं

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एक जुलाई को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस को संबोधित किया। 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस का मुख्य विषय 'अमृत कालः जीवंत भारत के लिए सहयोग के माध्यम से समृद्धि' है। श्री मोदी ने सहकारी विपणन, सहकारी विस्तार और सलाहकार सेवा पोर्टल के लिए ई-कॉमर्स वेबसाइट के ई-पोर्टल लॉन्च किए।

उपस्थित जनसमुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर सभी को बधाई दी और कहा कि देश 'विकसित और आत्मनिर्भर भारत' के लक्ष्य की दिशा में अग्रसर है। श्री मोदी ने भारत को दुनिया का अग्रणी दूध उत्पादक देश बनाने में डेयरी सहकारी समिति के योगदान और भारत को दुनिया के शीर्ष चीनी उत्पादक देशों में से एक प्रमुख देश बनाने में सहकारी समितियों की भूमिका का उल्लेख किया।

प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि डेयरी क्षेत्र में महिलाओं का योगदान लगभग 60 प्रतिशत है। इसलिए सरकार ने विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सहकारी क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने का फैसला किया। इसलिए पहली बार एक अलग मंत्रालय का गठन किया गया था और सहकारी समितियों के लिए बजट का आवंटन किया गया।

इस आयोजन से बड़ी संख्या में जुड़े किसानों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले 9 वर्षों में किसानों के कल्याण के लिए किए गए उपायों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अतीत में किसान बिचौलियों के चुंगल में फंसे थे, अब करोड़ों किसानों को सीधे उनके खातों में किसान सम्मान निधि मिल रही है। पिछले 4 वर्षों में पारदर्शी माध्यम से इस योजना के तहत 2.5 लाख करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए हैं। श्री मोदी ने बताया कि पिछले 9 वर्षों में सिर्फ उर्वरक सब्सिडी पर 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए गए हैं।

इस अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह, केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री श्री बी.एल. वर्मा, एशिया प्रशांत के लिए अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन के अध्यक्ष डॉ. चंद्रपाल सिंह यादव और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के अध्यक्ष श्री दिलीप संघानी भी उपस्थित थे।

छोटे वर्ग की आजीविका के लिए सहकारिता क्षेत्र में बहुत काम हुआ है: अमित शाह

17वें भारतीय सहकारी महासम्मेलन को संबोधित करते हुए केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने एक जुलाई को कहा कि भारत में सहकारिता आंदोलन आज़ादी से भी पहले लगभग 115 साल पुराना है और आज़ादी के बाद से ही सहकारिता क्षेत्र से जुड़े कार्यकर्ताओं की प्रमुख मांग थी कि एक अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन किया जाए।

श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 75 सालों से लंबित अलग सहकारिता मंत्रालय की मांग को पूरा करते हुए एक स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय का गठन किया। उन्होंने कहा कि एक स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय बनने और प्रधानमंत्री जी का सीधा मार्गदर्शन मिलने से सहकारिता के क्षेत्र में कई बदलाव संभव हुए हैं।

उन्होंने कहा कि कृषि ऋण वितरण में लगभग 29 प्रतिशत हिस्सा सहकारिता क्षेत्र का है, उर्वरक वितरण में 35 प्रतिशत, उर्वरक उत्पादन में 25 प्रतिशत, चीनी उत्पादन में 35 प्रतिशत, स्पिंडल के क्षेत्र में लगभग 30 प्रतिशत, दूध की खरीद, बिक्री और उत्पादन में लगभग 15 प्रतिशत, गेहूं की खरीद में 13 प्रतिशत, धान की खरीद में 20 प्रतिशत हिस्सा सहकारिता क्षेत्र का है।

श्री शाह ने कहा कि इनके अलावा कई क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटीज़, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसायटीज़, मत्स्य उत्पादन समितियां और सहकारी बैंक के माध्यम से विशेषकर छोटे वर्ग की आजीविका के लिए सहकारिता क्षेत्र में बहुत काम हुआ है। ■

प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के शहडोल में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मुक्ति मिशन का किया शुभारंभ

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एक जुलाई को मध्य प्रदेश के शहडोल में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मुक्ति मिशन का शुभारंभ किया और लाभार्थियों को सिकल सेल आनुवंशिक स्थिति कार्ड वितरित किए। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में लगभग 3.57 करोड़ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) कार्ड के वितरण कार्यक्रम की भी शुरुआत की। कार्यक्रम के दौरान श्री मोदी ने 16वीं सदी के मध्य में गोंडवाना की शासक रानी दुर्गावती को सम्मानित किया।

सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने रानी दुर्गावती को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मुक्ति मिशन आज शुरू किया जा रहा है, जो उनसे प्रेरित है। उन्होंने यह भी बताया कि मध्य प्रदेश के लोगों को 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी किये जा रहे हैं। श्री मोदी ने रेखांकित किया कि इन दो प्रमुख प्रयासों के सबसे बड़े लाभार्थी गोंड, भील और अन्य आदिवासी समाज के लोग हैं। उन्होंने इस अवसर पर मध्य प्रदेश की जनता और डबल इंजन सरकार को बधाई दी।

श्री मोदी ने कहा कि आज शहडोल की धरती से देश जनजातीय समुदाय के लोगों के जीवन को सुरक्षित करने, सिकल सेल एनीमिया से मुक्त करने और इस बीमारी से प्रभावित ढाई लाख बच्चों और परिवारों के जीवन बचाने का एक बड़ा संकल्प ले रहा है। जनजातीय समुदायों के साथ अपने व्यक्तिगत अनुभव को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने सिकल सेल एनीमिया के दर्दनाक लक्षणों और आनुवंशिक उत्पत्ति को रेखांकित किया।

श्री मोदी ने कहा कि सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन का यह अभियान अमृत काल का एक प्रमुख मिशन बनेगा। उन्होंने 2047 तक आदिवासी समुदायों और देश को सिकल सेल एनीमिया के खतरे से मुक्त करने का दृढ़ संकल्प व्यक्त किया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि बीमारी पूरे परिवार को प्रभावित करती है, क्योंकि बीमारी परिवार को गरीबी के जाल में फंसा देती है। गरीबी की अपनी पृष्ठभूमि का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार इस दर्द को समझती है और मरीजों की मदद के प्रति संवेदनशील है। इन प्रयासों से टीबी के मामलों में कमी आई है और देश 2025 तक टीबी को पूरी तरह खत्म करने की दिशा में काम कर रहा है।

प्रधानमंत्री ने विभिन्न बीमारियों के बारे में तथ्य प्रस्तुत करते हुए कहा कि 2013 में काला-जार के 11,000 मामले थे, जो अब घटकर एक हजार से भी कम हो गए हैं। 2013 में मलेरिया के 10 लाख मामले थे, जो 2022 में घटकर 2 लाख से भी कम हो गए हैं। इसी तरह कुष्ठ रोग के मामले भी 1.25 लाख से घटकर 70-75 हजार रह गए हैं। ■

पिछले 8 वर्षों में दूध उत्पादन में 51.05 प्रतिशत की वृद्धि

केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा 27 जून को जारी एक बयान के अनुसार पिछले 8 वर्षों में दूध उत्पादन में 51.05 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो 2014-15 के दौरान 146.3 मिलियन टन से बढ़कर 2021-22 के दौरान 221.06 मिलियन टन पर पहुंच गई। दूध उत्पादन पिछले 8 वर्षों में 6.1 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़ रहा है, जबकि विश्व दूध उत्पादन प्रति वर्ष केवल 1.2 प्रतिशत की दर से बढ़ा है। 2021-22 में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 444 ग्राम प्रतिदिन है, जबकि 2021 के दौरान विश्व औसत 394 ग्राम प्रतिदिन है।

गौरतलब है कि डेयरी सबसे बड़ी कृषि वस्तु है, जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में 5 प्रतिशत योगदान देती है और 8 करोड़ से अधिक किसानों को सीधे रोजगार देती है। भारत दूध उत्पादन में पहले स्थान पर है, जो वैश्विक दूध उत्पादन में 23 प्रतिशत का योगदान देता है। ■

प्रधानमंत्री ने गीता प्रेस के शताब्दी समारोह को किया संबोधित

'गीता प्रेस सिर्फ एक प्रिंटिंग प्रेस नहीं है, बल्कि एक जीवंत आस्था है'

गीता प्रेस भारत को संगठित करती है, भारत की एकजुटता को सशक्त करती है

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सात जुलाई को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में ऐतिहासिक गीता प्रेस के शताब्दी समारोह के समापन समारोह को संबोधित किया और चित्रमय शिव पुराण ग्रंथ का विमोचन किया। प्रधानमंत्री गीता प्रेस परिसर में लीला चित्र मंदिर भी गए और भगवान श्री राम के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की।

श्री मोदी ने कहा कि गीता प्रेस सिर्फ एक प्रिंटिंग प्रेस नहीं है, बल्कि एक जीवंत आस्था है। उन्होंने कहा कि गीता प्रेस का कार्यालय करोड़ों लोगों के लिए किसी मंदिर से कम नहीं है। साथ ही, श्री मोदी ने इस बात पर भी जोर दिया कि 1923 में गीता प्रेस के रूप में जिस आध्यात्मिक प्रकाश का उदय हुआ था, वह आज पूरी मानवता का मार्गदर्शक बन गया है।

गीता प्रेस से महात्मा गांधी के भावनात्मक जुड़ाव का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गांधी जी, गीता प्रेस के बारे में कल्याण पत्रिका के माध्यम से लिखते थे। उन्होंने कहा कि वो महात्मा गांधीजी ही थे, जिन्होंने यह सुझाव दिया था कि कल्याण पत्रिका में विज्ञापन प्रकाशित नहीं किए जाने चाहिए और इस सुझाव का अभी भी पालन किया जा रहा है।

श्री मोदी ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि देश ने गांधी शांति पुरस्कार प्रदान करके गीता प्रेस को अपना सम्मान दिया। यह पुरस्कार गीता प्रेस के योगदान और इसकी 100 साल पुरानी विरासत का सम्मान स्वरूप है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन 100 वर्षों में गीता प्रेस ने करोड़ों पुस्तकें प्रकाशित की हैं जो लागत से कम कीमत पर बेची जाती हैं और घर-घर पहुंचाई जाती हैं।

श्री मोदी ने रेखांकित किया कि गीता प्रेस जैसा संगठन न केवल धर्म और कर्म से जुड़ा है, बल्कि इसका राष्ट्रीय चरित्र भी है। गीता प्रेस भारत को संगठित करती है, भारत की एकजुटता को सशक्त करती है। ■

कमल संदेश के आजीवन सदस्य बनें

आज ही लीजिए कमल संदेश की सदस्यता और दीजिए राष्ट्रीय विचार के संवर्धन में अपना योगदान!

सदस्यता प्रपत्र

नाम : ....

पूरा पता : ....

....

.... पिन : ....

दूरभाष : .... मोबाइल : (1)................................ (2)................................

ईमेल : ....

सदस्यता						
	एक वर्ष	₹350/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी/अंग्रेजी)	₹3000/-	☐
	तीन वर्ष	₹1000/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी+अंग्रेजी)	₹5000/-	☐

(भुगतान विवरण)

चेक/ड्राफ्ट क्र. :.................................. दिनांक :............................ बैंक : ....

नोट : डीडी / चेक '**कमल संदेश**' के नाम देय होगा।

मनी आर्डर और नकद पूरे विवरण के साथ स्वीकार किए जाएंगे। (हस्ताक्षर)

कमल संदेश

अपना डीडी/चेक निम्न पते पर भेजें

डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पीपी-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003

फोन: 011-23381428 फैक्स: 011-23387887 ईमेल: kamalsandesh@yahoo.co.in

नई दिल्ली में 1 जुलाई, 2023 को 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस में सहकारी विपणन, सहकारी विस्तार और सलाहकार सेवा पोर्टल के लिए ई-कॉमर्स वेबसाइट का शुभारंभ करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

शहडोल (मध्य प्रदेश) में 1 जुलाई, 2023 को राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

भोपाल (मध्य प्रदेश) में 27 जून, 2023 को रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से 5 नयी वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

नई दिल्ली में 30 जून, 2023 को दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में शामिल होने के लिए जाते वक्त दिल्ली मेट्रो में लोगों के साथ बातचीत करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

काहिरा (मिस्र) में 25 जून, 2023 को मिस्र के राष्ट्रपति श्री अब्देल फतह अल-सिसी से मुलाकात करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

काहिरा (मिस्र) में 25 जून, 2023 को अल-हकीम मस्जिद का भ्रमण करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

कमल संदेश

अब इंटरनेट पर भी उपलब्ध

लॉग इन करें:

www.kamalsandesh.org

राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

@Kamal.Sandesh

@KamalSandesh

kamal.sandesh

KamalSandeshLive

प्रेषण तिथि: (i) 1-2 चालू माह (ii) 16-17 चालू माह

डाकघर: लोदी रोड एचओ., नई दिल्ली **"रजिस्टर्ड"**

36 पृष्ठ कवर सहित

प्रकाशन तिथि: 14 जुलाई, 2023

आर.एन.आई. DELHIN/2006/16953

डी.एल. (एस)-17/3264/2021-23

Licence to Post without Prepayment

Licence No. U(S)-41/2021-23

छायाकार: अजय कुमार सिंह